सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 242, नई दिल्ली । मंगलवार, 12 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 जल्द आएगा DUSU चुनाव का रिजल्ट.....
06 हवा स्वच्छ रखने में नागरिकों की की भूमिका
08 'चुनाव और शादी पर भी पटाखों पर लगे बैन'

क्या बस मार्शल अब अपनी एकता रख पाएंगे या बट जाएंगे

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की बसों में मार्शल की कार्य में लगे सभी जा सेवक/ सेविकाओं ने अपनी नौकरी वापिस पाने के लिए जितनी एकता अब तक दिखा कर जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासक उपराज्यपाल पर दबाव बनाया हुआ था वह अब रह पाएगा, इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जिस तरह अपनी जरूरत के अनुसार चार महीने के काम पर रखने की घोषणा कर दी है उसके बाद यह उम्मीद कम है की सभी पूर्व में बस मार्शल की सेवा देने वाले इस मिले ही मौके से मुंह मोड़ सकेंगे और इस चार महीने के कार्य के लिए आवेदन नहीं करेंगे। अगर कुछ बस मार्शलों ने भी इस कार्ड के लिए आवेदन कर दिया तो यह सिद्ध हो जाएगा की बास मार्शलों में अब एकता नही रही। एकता नही तो वापिस वह बस मार्शल की नौकरी भी नही।

आपको जानकारी हेतु बता दें की पूर्व में दिल्ली की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद पर रही शीला दीक्षित द्वारा भी वॉट बैंक को बनाने की उद्देश्य से भागीदारी नाम का एक बड़ा ग्रुप बना रखा था जिसमें दिल्ली की सभी आर डब्ल्यू ए सदस्य थी पर उनके साथ ही वह ग्रुप समाप्त हो गया था। ठीक उसी प्रकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अपने शुरुआती समय में अपने वोट बैंक को बनाने के लिए सिविल डिफेंस/ बस मार्शल के पदों पर जनता को नियुक्त करा था। अब आम आदमी पार्टी अपने आप में एक सक्षम पार्टी के रुप मे व्यापक हो चुकी हैं और अब उसको उन

व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस नहीं होती जो उनके सामने विरोध में खड़े हो।

आज की दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह सिद्ध कर दिखाया है की सरकार को अगर किसी कार्य के लिए जन मानस की जरूरत है तो जरूरत से अधिक दिल्ली में रह रहे जन मानस उसके लिए तत्पर हैं तो उन व्यक्तियों की क्या आवश्यकता जो विरोध करना सीख चुका। यह घोषणा मात्र बास मार्शलों की एकता को तोड़ना है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सिविल डिफेंस के जो व्यक्ति विभागों में कार्यरत थे उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था क्योंकि उनमें एकता नही थी। **अब जल्दी ही देखने में आ जाएगा की बस मार्शलों की एकता बचती हैं यह टूटती है।**

क्या है हैप्पी कार्ड स्कीम? लोगों में हो रही है लोकप्रिय; जिले के 6 हजार से ज्यादा लोग उठा रहे हैं लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड) के तहत गुरुग्राम में 6274 लोग निशुल्क बस यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है तो वे हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्डधारक हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकते हैं। आगे विस्तार से जानिए पूरी योजना के बारे में।

गुरुग्राम। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड) का जिले के 6,274 लोग लाभ उठा रहे हैं। जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है, वह हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

कार्ड बांटने में लगी हैं पांच टीमें

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि योजना के अनुसार, हैप्पी कार्ड धारक नागरिक रोडवेज की बसों में हर साल एक हजार किलोमीटर तक निःशुल्क सफर कर सकता है। कार्ड का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। एटीएम की तरह नीले रंग का दिखाई देने वाला हैप्पी कार्ड बांटने के लिए परिवहन विभाग ने पांच टीमें बनाई हुई हैं जो कि गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी व फरुखनगर में काम कर रही हैं।

8,789 लोगों ने किया आवेदन

कार्ड बनवाने के लिए 8,789 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इनमें से 6,274 को कार्ड दिया जा चुका है और 2505 कार्ड दिए जाने बाकी रह गए हैं। जनसेवा पोर्टल के माध्यम से इस कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद रोडवेज विभाग में जाकर यह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

50 रुपये लिया जाता है शुल्क

परिवहन विभाग की ओर से एक ओटीपी नंबर आवेदक के मोबाइल पर भेजा जाता है। ओटीपी नंबर डालते ही आवेदक का हैप्पी कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। हर कार्ड पर 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है।

एक साल बाद कार्ड का नवीनीकरण करा सकते हैं लोग

कार्डधारक परिवार का सदस्य, जिसका नाम फैमिली आईडी में दर्ज है, वह इससे यात्रा कर सकता है। परिवहन विभाग की बसों में परिचालक अपनी स्वीप मशीन से कार्ड को स्कैन करते हैं और यात्रा का विवरण कार्डधारक के रिकॉर्ड में अपलोड हो जाता है। एक साल पूरा होने के बाद नागरिक अपने हैप्पी कार्ड का नवीनीकरण करवा सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो ने शुरू की बाइक टैक्सी, आपके सफर को आसान बनाएंगी महिला ड्राइवर; इन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है जिसमें महिला यात्रियों के लिए विशेष बाइक टैक्सी शामिल हैं जिन्हें महिला चालक चलाएंगी। इस सेवा से यात्री मेट्रो के मोबाइल ऐप डीएमआरसी मोमेंटम (दिल्ली सारथी 2.0) से बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे। महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसकी जीपीएस से निगरानी होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। इसमें महिला यात्रियों के लिए विशेष बाइक टैक्सी शामिल है जिसे महिला चालक चलाएंगी। इस सेवा के शुरू होने से यात्री मेट्रो के मोबाइल एप डीएमआरसी मोमेंटम (दिल्ली सारथी 2.0) से बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसकी जीपीएस से निगरानी होगी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने सोमवार को इस सेवा की शुरुआत की। राइडर सेवा सभी यात्रियों के लिए है। वहीं, महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा का नाम शीराइड्स दिया गया है। डीएमआरसी का कहना है कि महिलाओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखकर शीराइड्स सेवा शुरू की गई है। इससे महिला बाइक चालकों को कमाने का अवसर भी मिलेगा।

इन मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक पर्यावरण अनुकूल हैं। प्रशिक्षित और सत्यापित चालक रखे गए हैं। यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस से इसकी निगरानी होगी। पहले चरण में 12 मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर-21, द्वारका सेक्टर-10, द्वारका सेक्टर-14, द्वारका मोड़, जनकपुरी पश्चिम, उत्तम नगर पूर्व, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, कीर्ति नगर, करोल बाग, मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम और पालम से सुबह आठ से रात नौ बजे तक बाइक टैक्सी सुविधा उपलब्ध होगी।

इन स्टेशनों से तीन से पांच किलोमीटर के क्षेत्र के लिए यह सुविधा होगी। एक माह बाद 100 से अधिक और तीन माह में सभी 250 मेट्रो स्टेशनों से यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

क्या होगी शुल्क?

न्यूनतम शुल्क 10 रुपये, उसके बाद पहले दो किलोमीटर के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर तथा उसके बाद आठ रुपये प्रति किलोमीटर।

पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में कैसे बदलें? लोगों का सरकार से सवाल, दिल्ली में 5 साल बाद भी नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है लेकिन लोगों के पास अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का कोई विकल्प नहीं है। विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प दिया था लेकिन पांच साल बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पूछ रहे हैं वे पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट कहां लगवाएं।

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके 59 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। मगर विभाग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं खड़ी कर सका है कि लोग अपने पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदल सकें।

हालांकि कहने के लिए विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का एक विकल्प जनता को दे दिया है, मगर पांच साल बाद भी विभाग जहां का तहां खड़ा है।

अधिकारी नहीं दे रहे जवाब

लोग पूछ रहे हैं अपने पुराने वाहन में इलेक्ट्रिक किट कहां लगवाएं। परिवहन विभाग के अधिकारी इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कारों में इलेक्ट्रिक किट लगवाने की प्रक्रिया बहुत महंगी है और कार में इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए कम से कम छह लाख का खर्च आता है।

सफलता पर संशय

उन्होंने कहा कि अभी तक किसी अन्य राज्य में भी यह व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता पर संशय है। इसलिए यह स्कीम आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्होने कहा कि दो पहिया में इस पर विचार किया जा सकता है। मगर यह नीतिगत मामला है।

परिवहन विभाग को मिला था कंपनियों का साथ

इस स्कीम की बात करें तो इसे लेकर परिवहन विभाग ने 2019 में बैठक बुलाई थी और इस मुद्दे पर उनकी राय ली थी। उस समय करीब 11 कंपनियों ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताते हुए आगे आने की बात कही थी। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक किट लगाने वाली इन कंपनियां का पैनल बना दिया था।

ट्रायल सफल रहा

कंपनियों ने दावा किया था कि उन्होंने कारों और दोपहिया में इसका ट्रायल किया है जो सफल रहा है। विभाग के अधिकारी ने कहा है कि इस प्रयोग को लेकर सकारात्मक सोचने की जरूरत है। कुछ समय की बात है कि हम कारों को डीजल से इलेक्ट्रिक में करवाना शुरू करवा देंगे।

इसके लिए 11 कंपनियों का पैनल बनाया गया था। कहा गया था कि उनसे संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। मगर योजना आगे नहीं बढ़ सकी है।

बंगलुरू की कंपनी स्कूटर में लगाएगी बैटरी

बंगलुरु की कंपनी ग्रीन टाइगर ने स्कूटर को इलेक्ट्रिक में बदलने का प्रमाणपत्र हासिल किया है। कंपनी बंगलुरु में काम कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष दोकनिया ने कहा कि हम दिल्ली में काम करने के लिए तैयार हैं।

पुराने वाहनों के लिए टैक्स में दे छूट

उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार के साथ हुई बातचीत में हमने सुझाव दिया है कि जिस तरह से सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में छूट दे रही है, इसी तरह पुराने वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदलने पर पंजीकरण व टैक्स में छूट दे। उन्होंने कहा कि पुराने दो पहिया वाहन को स्क्रैप कराने और नए दो पहिया खरीदने पर नीति में सब्सिडी देने का प्रविधान किया है, जो कुल मिलाकर 13 हजार बैठता है।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार 13 हजार की जगह दो पहिया स्कूटर या स्कूटी में इलेक्ट्रिक लगवाने पर अगर 10 हजार सब्सिडी दे देती है तो यह किट 20 हजार के करीब लोगों को पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम यह स्कीम देने को भी तैयार हैं कि इस 20 हजार में से आधे पैसे देने के बाद इसे किस्त पर दे दिया जाएगा।

यानी 10 हजार में ही लोग अपने दो पहिया को इलेक्ट्रिक किट में बदल सकेंगे। जिसकी लाइफ कम से कम 15 साल मानी गई है। यानी बहुत कम पैसे में उसे एक नई तरह की स्कूटी मिल जाएगी।

तिपहिया को इलेक्ट्रिक में बदलने का काम कर रहे हैदराबाद की कंपनी जीरो-21 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानी श्रीनिवासन ने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ लंबे समय से बात कर रहे थे, मगर कहीं कुछ होता दिख नहीं रहा है तो अब कुछ माह से बात नहीं हुई है।

वह कहते हैं कि उनकी कंपनी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के तिपहिया को साढे.चार घंटे में इलेक्ट्रिक में बदल देती है। परिणाम बेहतर आ रहे हैं। तीन से लेकर चार रुपये एक किलोमीटर चलने वाला तिपहिया अब 75 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्च पर चल रहा है।उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इस मामले में सब्सिडी देनी चाहिए।

पुणे में छोटा हाथी में इलेक्ट्रिक किट लगाने के कार्य के विशेषज्ञ राहुल चंदवानी कहते हैं कि इस बारे में हम लोग दिल्ली परिवहन विभाग से लगातार संपर्क कर रहे थे। मगर दिल्ली परिवहन विभाग से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हम लोगों ने संपर्क करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य जितना आसान दिख रहा है, यह उतना आसान नहीं है।पहले तो वाहन का पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा।

पत्नी के साथ विदेश घूमने का सपना होगा पूरा, जेब भी ज्यादा नहीं होगी ढीली

अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बजट के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन जगहों पर घूमने के लिए आपको करीबर 1 से 2 लाख रुपए के बीच खर्च आएगा।

नई दिल्ली। ऐसा शायद ही कोई होगा, जिसको विदेश घूमने का शौक नहीं होगा। हर कोई साल में एक बार फॉरेन ट्रिप तो जरूर करना चाहता होगा। लेकिन कई लोग बजट के कारण विदेश नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बजट के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपके लिए कुछ ऐसे सस्ते विदेश ट्रिप लेकर आए हैं, जो आपके बजट में फिट बैठ जाएंगे।

आप इन जगहों पर घूमने के साथ-साथ एक से एक बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बता दें कि इन जगहों पर घूमने के लिए आपको करीबर 1 से 2 लाख रुपए के बीच खर्च आएगा। तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में...

सामोआ

दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित सामोआ एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, जोकि हवाई और न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है। सामोआ पोलिनेशिया का भी हिस्सा है और कई छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। सामोआ अपने हरे-भरे नजाओं, जीवंत संस्कृति और प्राचीन समुद्र तटों के लिए जाना जाता है।

बारबाडोस

बारबाडोस पूर्वी कैरिबियन में स्थित है, यह जगह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, समुद्र तटों और जलवायु के लिए जानी जाती है। इस देश की राजधानी ब्रिजटाउन है। जो सबसे बड़े शहर के रूप में फेमस है। बारबाडोस अपने सफेद-रेतील, कोरम रीफ्स और क्रिस्टल वॉटर के लिए फेमस है। यह पर्यटकों के लिए फेमस डेस्टिनेशन है। यहां पर आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी कई एक्टिविटीज कर सकते हैं।

नेपाल

नेपाल भी अपने खूबसूरत नजारों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेपाल की हिमालय रेंज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां पर हिमालय की ऊंची-ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट दुनियाभर में फेमस है। यहां की राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडी देश की आर्थिक, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बना हुआ है।

भूटान

बता दें कि भूटान एक छोटा लैंडलॉक राज्य है। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है, जोकि भारत और चीन से सीमाबद्ध है। यहां पर हैरान कर देने वाले पहाड़ी नजारों, पर्यावरण संरक्षण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। भूटान को 'अंतिम शांगरी-ला' के रूप में जाना जाता है।

मालदीव

मालदीव भी कपल्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। यह भारतीय महासागर में स्थित है। बता दें कि मालदीव श्रीलंका और भारत के दक्षिण-पश्चिम की तरफ पड़ती है। यहां पर हैरान कर देने वाले सफेद-रेतीले समुद्र तटों, समुद्री जीवन और क्रिस्टल वॉटर के लिए जाना जाता है। यह देश की राजधानी माले दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है।

मॉरीशस

मॉरीशस भारतीय महासागर में स्थित है। यह फिरोजी लैगून, प्राचीन समुद्र तटों और हरे-भरे जंगलों के लिए फेमस है। यह पर्यटकों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। जोकि प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का मिश्रण है। मॉरीशस द्वीप की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस देश के आर्थिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है।

कोयले से बने चारकोल फेस मास्क से मिलेगी दमकती बेदाग त्वचा, घर पर ऐसे बनाकर करें तैयार

हर फंक्शन और त्योहारों के मौके पर लोग अपने स्किन का खास ख्याल रखते हैं। वहीं धूल, मिट्टी, पसीने और पॉल्यूशन का भी स्किन पर बुरा असर पड़ता है। फिर भले ही आप फेस वॉश के इस्तेमाल से चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है, लेकिन इसकी संभावना अधिक है कि केमिकल वाले ये फेस वॉश आपकी त्वचा को ड्राई कर सकते हैं या फिर पिंपल्स ला सकते हैं। आमतौर पर स्किन से गंदगी साफ करने के लिए हमारी पहली चॉइस चारकोल फेसवॉश होती है।

बता दें कि मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स में कई केमिकल्स मिले होते हैं। अगर हम आपसे कहें तो आप घर पर 2 टुकड़े कोयले की मदद से फेस मास्क बना सकते हैं। चेहरे के अंदर तक की गंदगी को साफ कर सकते हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको घर पर कोयले से बने फेस मास्क बनाने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।

स्किन बेनिफिट्स

फेस पर चारकोल का इस्तेमाल करने से गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। यह हमारी त्वचा से एक्स्ट्रा तेल को साफ करने, स्किन टोन को इवन करने और पोर्स को क्लीन करने में मदद करता है। इससे आपकी त्वचा हमेशा चमकती रहती है।

चारकोल फेस मास्क की सामग्री

कोयला- 2 टुकड़े (3-3 इंच के)
नींबू- 2
मुल्तानी मिट्टी- -1/2 चम्मच
एलोवेरा जेल- 1 चम्मच
गुलाब जल- जरूरत अनुसार

नोट- आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी की जगह इसमें बेसन या फिर दही डाल सकते हैं। वहीं गुलाबजल न होने पर आप इसमें नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे बनाएं चारकोल फेस मास्क

सबसे पहले एक बाउल में एक चम्मच कोयला पाउडर, एलोवेरा जेल, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और जरूरत अनुसार गुलाबजल डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें।

ऐसे करें अप्लाई

इस चारकोल फेस को 10 मिनट के लिए चेहरे पर अप्लाई करें और इसको सूखने के लिए छोड़ दें।

फिर फेस वॉश कर लें, आप देखेंगे कि चेहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और चेहरे पर निखार भी आएगा।

आप इसको सप्ताह में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा साफ होगी।

रोज नमकीन चावल खाकर बोर हो गए हैं, तो कॉर्न पुलाव करें ट्राई, नोट करे रेसिपी

रोजाना एक जैसा खाना खाकर हम सभी बोर हो जाते है। खाने में अगर नयापन न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इस तरह से घर में कॉर्न पुलाव बनाएंगी तो सभी लोग इसे खूब पसंद करेंगे। आइए जानते हैं कॉर्न पुलाव की रेसिपी।

नई दिल्ली। सुबह-शाम हर समय एक जैसा खाना खाकर हम सभी बोर हो जाते हैं। जिस वजह से बाहर का जंक फूड अच्छा लगने लगता है। अगर आप भी घर पर एक ही टाइफ के नमकीन चावल खाकर बोर हो गए हैं तो आप एक बार कॉर्न पुलाव जरुर खाएं। जिन लोगों को स्वीट कॉर्न खाना पसंद हैं उन्हें ये पुलाव जरुर खाना चाहिए। आइए आपको कॉर्न पुलाव बनाने का सबसे इजी तरीका बताते हैं।

सामग्री

- बासमती राइस
- अमेरिकन कॉर्न
- घी या सरसों का तेल
- प्याज
- अदरक लहसुन का पेस्ट
- नमक
- हरी मिर्च
- लौंग
- गर्म पानी
- हरा धनिया
- नींबू का रस
- अलग रंग की शिमला मिर्च
- कद्दूकस किया नारियल

कॉर्न पुलाव बनाने की विधि

सबसे पहले आप बासमती चावल को धो ले कम से कम 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद हरी मिर्च, धनिया पत्ती को पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन लें, उसमें जैतून का तेल डालें। फिर तेल गर्म होने पर इसमें डालें जीरा, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। अब आप इसे अच्छे से भूनें और इसके बाद अमेरिकन कॉर्न डालें। चावल को छान लें और इसे पैन में डालें। अब मिक्स करें और फिर गर्म पानी में थोड़ा नमक डालें और 15 मिनट तक पकाएं। चावल पकने के बाद नींबू का रस डालें। आखिर में आप अलग-अलग रंग की शिमला मिर्च को भून कर डाल दें। धनिया पत्ती और कद्दूकस किया नारियल से गर्निश करें और फिर सर्व करें।

पार्टी के बाद अपनी त्वचा को डिटॉक्स कैसे करें, इन 7 टिप्स को फॉलो कीजिए

जब हम सभी किसी पार्टी में जाते हैं तो हैवी मेकअप जरुर करते जाते हैं। भारी मेकअप देर रात त्वचा में लगा रहता है। पार्टी में ज्यादा खाना खाने से आपकी त्वचा भी काफी सुस्त पड़ सकती है। ऐसे में आपके चेहरे को डिटॉक्स करना भी जरुरी होता है। आइए जाने कैसे करें चेहरे को डिटॉक्स।

नई दिल्ली। पार्टियां करना आखिर किस को पसंद नहीं है। हम सभी लेट नाइट पार्टियां या नॉर्मल पार्टी में जरुर जाते हैं। जहां अपने चेहरे पर काफी मेकअप करके जाते हैं। भारी मेकअप चेहरे पर देर रात तक रहना और पार्टी का स्वादिष्ट भोजन खाने से आपकी त्वचा एकदम सुस्त, थकी हुई बन जाती है, जो डिटॉक्स की जरूरत वाली दिखने लगती है। आइए जानते हैं किस तरह से अपने चेहरे को डिटॉक्स कर सकते हैं।

हाइड्रेशन जरुरी है

अपने चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए खूब पानी पिएं और शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कैमोमाइल जैसी हर्बल टी का सेवन जरुर करें। हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पिएं।

चेहरे के लिए डबल सफाई जरुरी

जब किसी पार्टी से लौटकर आते हैं, तो केवल माइसेलर पानी और मेकअप वाइप्स पर निर्भर न रहें। मेकअप को हटाने के लिए क्लींजिंग ऑयल या बाम से शुरुआत करें। इसके बाद चेहरे के बैक्टीरिया साफ करने के लिए आप सौम्य क्लींजर से फेस को क्लीन करें।

डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क इस्तेमाल करें

चेहरे की अशुद्धियां निकालने के लिए और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सप्ताह में दो बार मिट्टी या चारकोल मास्क लगाएं। चेहरे के रोमछिद्रों को क्लीन करने के लिए 10-15 मिनट तक डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क लगाएं। फिर चेहरे को साफ पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी।

सनस्क्रीन जरुर लगाएं

सनस्क्रीन लगाने से काले-धब्बे और पिगमेंटेशन को रोकता है। सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा चमकदार बनती है और पार्टी के लिए भी तैयार रहती है।

आईस फेशियल करें

अपने चेहरे पर ठंडे टी बैग्स या खीरे से देर रात की सूजन को कम करने के लिए और सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए चेहरे की मालिश करें। जिससे त्वचा तरोताजा हो जाएगी। आप बर्फ टुकड़े थोड़ी देर रखकर उस पानी से चेहरे को धो सकते हैं या फिर सिकाई कर सकते हैं।

नींद को प्राथमिकता दें

अच्छी त्वचा के लिए चेहरे की मरम्मत के लिए नींद लेना भी काफी जरुरी है। अपनी त्वचा को प्राकृतिक रुप से पुनर्जीवित करने में मदद के लिए बढ़िया आराम से सोएं।

सौम्य एक्सफोलिएशन जरुरी

मृत कोशिकाओं को हटाने और ब्रेकआउट से बचने के लिए पार्टी के एक या दो दिन बाद हल्के एक्सफोलिएंट का उपयोग करें, जिससे आपकी त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाएगी।

रात को खांसी आपको सोने नहीं देती, तो इन घरेलू उपाय को फॉलो करें

अगर आपको भी रात को खांसी आती हैं, तो सोने से पहले हल्दी का साथ शहद का सेवन करें। हल्दी और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल व एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं।

सर्दियों की शुरुआत अपने साथ सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं लेकर आती है। कुछ लोगों की खांसी रात में बदतर हो जाती है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है और अगले दिन उन्हें थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। यदि आपको बदलते मौसम के साथ रात में खांसी बढ़ जाती है, तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन घरेलू उपायों से खुद की खांसी को रोकने में मदद कर सकते हैं।

रात के समय खांसी के लिए आयुर्वेदिक इलाज

- अगर आपको रात को खांसी होती है, तो आप सोने से पहले हल्दी के साथ शहद का सेवन करने का प्रयास जरुर करें। ये दोनो ही एंटीफंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। आपको हल्दी और शहद एक साथ लेने से खांसी में आराम मिलेगा।

शहद और हल्दी की ड्रिंक कैसे बनाएं

- शहद और हल्दी का सेवन करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी को उबाल लें। उबले हुए पानी में दो चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। ध्यान रहे कि ज्यादा गर्म पानी में शहद मिलाने से बचें, क्योंकि शहद को उच्च तापमान के संपर्क में लाने से इसके लाभकारी गुण कम हो सकते हैं। मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं, छान लें और चाय की तरह इसका आनंद लें।

शहद और हल्दी के घरेलू उपचार के फायदे

यह ड्रिंक आपके मुंह के छालों को शांत कर सकता है और सर्दियों में इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार है।

अन्य घरेलू उपचार

- जब आप सोते हैं तो उससे पहले नमक के पानी से गरारे करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी।
- नींबू और शहद का मिश्रण रात के समय खांसी से राहत दिला सकता है, लेकिन बच्चों को यह न दे।
- भुनी हुई अदरक गले की खराश से राहत दिला सकती है और खांसी को कम कर सकती है।
- हल्दी वाला दूध सबसे बेहतरीन उपायो में से एक है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो छींक को कम करने और बेहतर नींद को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

व्हाट्सऐप की इस ट्रिक से छुपा सकते हैं अपनी प्राइवेट चैट, यहां जानें आसान तरीका

चैट्स को लॉक करने के लिए ये फीचर काफी कमाल का है, लेकिन इसकी एक कमी ये है कि लॉक चैट्स को वॉट्सऐप के लॉक्ड चैट फोल्डर में जाकर देखा जा सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए वॉट्सऐप ने सीक्रेट कोड फीचर को लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से आप अपने लॉक्ड चैट्स की प्राइवेसी को और बेहतर कर सकते हैं।

WhatsApp ने यूजर्स की प्राइवेसी के लिए चैट लॉक फीचर रोलआउट किया था। चैट्स को लॉक करने के लिए ये फीचर काफी कमाल का है, लेकिन इसकी एक कमी ये है कि लॉक चैट्स को वॉट्सऐप के लॉक्ड चैट फोल्डर में जाकर देखा जा सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए वॉट्सऐप ने सीक्रेट कोड फीचर को लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से आप अपने लॉक्ड चैट्स की प्राइवेसी को और बेहतर कर सकते हैं। ये फीचर यूजर्स को चैट लिस्ट से लॉक्ड चैट्स फोल्डर को हाइड करने का ऑप्शन देता है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद लॉक्ड चैट्स को देखने के लिए सर्च बार में आपको सीक्रेट कोड को टाइप करना होगा।

ऐसे सेट करें सीक्रेट कोड

1. वॉट्सऐप ओपन करें और लॉक्ड चैट्स फोल्डर में जाएं।
2. अब ऊपर राइट साइड में दिए गए ओवरफ्लो मेन्यू पर टैप करें।
3. चैट लॉक सेटिंग्स को सेलेक्ट करें।
4. सीक्रेट कोड पर टैप करें।
5. कोड एंटर करें। इस कोड के लिए आप लेटर्स या इमोजी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
6. नेक्स्ट पर टैप करके सीक्रेट कोड को फिर से एंटर करें।
7. सीक्रेड कोड्स मैच का मैसेज दिखने पर Done सेलेक्ट करें।

इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका सीक्रेट कोड सेटअप हो जाएगाय आप चाहें, तो चैट लिस्ट से लॉक्ड चैट्स को हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैट लॉक सेटिंग्स में वापस जाकर हाइड लॉक्ड चैट्स के बगल में दिए गए टॉगल पर टैब करना होगा। लॉक्ड चैट्स को आप चैट्स टैब में सीक्रेट कोड एंटर करना होगा। अगर आप अपना सीक्रेट कोड भूल गए हैं और लॉक्ड चैट्स को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लॉक्ड चैट्स को क्लियर करना होगा। इसके लिए आप सेटिंग्स में दिए गए प्राइवेसी ऑप्शन में जाकर चैट लॉक पर टैब करें। यहां आपको अनलॉक और क्लियर लॉक्ड चैट्स का ऑप्शन मिल जाएगा।

गूगल पर भूलकर भी ना सर्च करें यह लाइन, वरना हो जाएजा सबकुछ हैक

अगर आप इंटरनेट का यूज करते तो इस बारे में पता होना चाहिए। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। SOPHOS ने कहा कि जब यूजर्स सर्च रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तब आपकी निजी और बैंक की जानकारी Gootloader नाम के एक प्रोग्राम की मदद से ऑनलाइन शेयर किया जाता है।

आजकल साइबर ठग इंटरनेट यूजर्स को नए तरीके ठगने के लिए अपना रहे हैं। दरअसल, हैकर्स ऐसे लोगों का निशाना बना रहे हैं, जो इंटरनेट पर खास शब्दों को सर्च करते हैं, तो इसके बाद लिंक पर क्लिक करते ही उनकी निजी जानकारी ऑनलाइन शेयर हो जाती है। कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम की मदद से यूजर से कंप्यूटर का कंट्रोल भी छीन लेता है।

जानें क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साइबर सिक्युरिटी कंपनी SOPHOS ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है। कंपनी ने बताया है कि जो लोग गूगल पर Are Bengal Cats legal in Australia? सर्च करने पर यूजर्स का कथित तौर पर पर्सनल डेटा ऑनलाइन पोस्ट हो रहा है। यह सर्च करने के बाद मिलने वाली पहली लिंक पर क्लिक करने से हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने बताया है कि 6 शब्दों को सर्च करने वाले यूजर्स के साइबर हमले का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। SOPHOS ने बताया कि, 'वैध मार्केटिंग के रुप में पेश की जा रही लिंक्स या मेलीशियस एडवेयर पर क्लिक करने के लिए यूजर को लुभाया जाता है।

आपको बता दें कि वैध गूगल सर्च के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। कंपनी ने जो चेतावनी जारी की उसके अनुसार, हैकर्स उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो खासतौर से Australia को सर्च करते हैं। SOPHOS ने बताया कि, यूजर्स सर्च रिजल्ट पर क्लिक करता है तो उनकी निजी और बैंक की सारी डिटेल्स Gootloader नाम के एक प्रोग्राम की मदद से ऑनलाइन शेयर करते हैं।

SEO poisoning क्या है जिससे निशाना बना रहे

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर ठग एसईओ पॉइजनिंग को अपना रहे जिससे हैकिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसी तकनीक का प्रयोग कर रहे, जिसकी मदद से अपराधी सर्च इंजन के रिजल्ट्स में छेड़छाड़ कर उन वेबसाइट्स को ऊपर पहुंचा देते हैं, जिन्हें वो चला रहे हैं। SOPHOS ने कहा है कि इससे शिकार होने के बाद यूजर्स अपना पासवर्ड तुरंत बदल देना चाहिए।

दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण, आप भी करते हैं सामना; CSE की स्टडी में सामने आई नई वजह

सुषमा रानी

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का एक प्रमुख कारण है ट्रैफिक जाम। शाम के समय यह समस्या और भी विकराल हो जाती है। सीएसई की एक हालिया स्टडी में सामने आया है कि दोपहर की तुलना में शाम को नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर दोगुना तक बढ़ जाता है। स्टडी में यह भी पाया गया कि त्योहारों के दौरान प्रदूषण में 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है।

नई दिल्ली। यातायात जाम परेशानी का ही नहीं, दिल्ली के प्रदूषण में वृद्धि की भी वजह बन रहा है। खासकर शाम के समय ऐसी स्थिति कमोबेश रोज बन रही है। त्योहारों के दौरान यह वृद्धि और बढ़ जाती है। बाटलनेक व वाहनों की अधिकता से लगने वाले इस जाम से उत्पादकता और ईंधन की हानि भी हो रही है।

लीड्स विश्वविद्यालय यूके द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक 2010 में भीड़भाड़ के कारण 1.6 मिलियन अमेरिकी डालर सालाना ईंधन की बर्बादी हुई थी। आईआईटी मद्रास ने वर्ष 2015 में अनुमान लगाया था कि 2025 तक यह हानि 12,003 मिलियन और 2030 तक 14,658 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।

दोपहर की तुलना में रात को दोगुना हो जाता नाइट्रोजन

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) द्वारा इसी साल 27 अक्टूबर से एक नवंबर के दौरान छह दिनों की विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 12 से अपराहन चार बजे के बीच वाहनों की औसत गति 21 किमी प्रति घंटा रहती है। इसके चलते वाहनों से होने वाले उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर भी हवा में कम रहता है, लेकिन शाम पांच से रात नौ बजे के बीच सड़कों पर वाहनों की अत्यधिक भीड़ होती है। इसके चलते वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं। जगह-जगह जाम लग जाता है। वाहनों की औसत गति 15 किमी प्रति घंटे तक की हो जाती है। नतीजा, दोपहर की तुलना में शाम को नाइट्रोजन आक्साइड का स्तर दोगुना तक बढ़ जाता है।

वुप्पर्टल विश्वविद्यालय जर्मनी के टूमी ई बस मिशन के अनुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 11 लाख वाहनों का आना-जाना होता है। यहां पहले से ही शहरों में पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है।

त्योहार में पांच से 10 प्रतिशत तक और हो जाती है वृद्धि

त्योहारों के दिनों में प्रदूषकों में और वृद्धि होने लगती है। 15 सितंबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में प्रमुख सड़कों पर गूगल से आंकड़ों के अवलोकन पर वाहनों की गति में कमी का पता चलता है। इस दौरान सप्ताह के दिनों में सुबह की अधिकतम गति में 40.8 प्रतिशत जबकि शाम की गति में 57.9 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं, सप्ताहांत में सुबह की अधिकतम गति में 27.6 प्रतिशत और शाम की गति दो प्रतिशत कम हो गई। मतलब, दुर्गा पूजा वाले सप्ताह में पांच से आठ प्रतिशत और दीवाली से पहले की अवधि में सात से 10 प्रतिशत तक प्रदूषण और बढ़ गया।

वाहन नाइट्रोजन आक्साइड के स्तर का प्रमुख स्त्रोत

भीड़भाड़ व जाम में फंसे वाहन सड़कों पर अपने सामान्य उत्सर्जन से कई गुना अधिक उत्सर्जन उगल सकते हैं। चूंकि वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर के प्रमुख स्त्रोत हैं, इसलिए वाहनों और नाइट्रोजन आक्साइड के स्तरों में प्रति घंटा परिवर्तन के बीच एक मजबूत संबंध है। 2018 में टेरी एआरआई की उत्सर्जन सूची से भी पता चलता है कि नाइट्रोजन आक्साइड के उत्सर्जन में परिवहन का हिस्सा सर्वाधिक 81 प्रतिशत और इसके बाद बिजली संयंत्रों का सात प्रतिशत तक है।

दिल्ली के तीन इलाकों की हवा हुई 'गंभीर', छह दिनों तक झेलने के लिए रहें तैयार

दिल्ली की हवा फिर से हुई खराब तीन इलाकों का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले छह दिनों के दौरान हवा की रफ्तार 10 किमी से नीचे ही रहेगी। मौसमी परिस्थितियां भी प्रतिकूल रहेंगी। ऐसे में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। जानिए दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का हाल।

नई दिल्ली। हवा की रफ्तार में थोड़ा तेज होने से रविवार को सात दिनों बाद 350 से नीचे आया दिल्ली का एक्यूआई सोमवार को फिर से 350 के ऊपर पहुंच गया। वायु गुणवत्ता लगातार 13वें दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बनी रही। राजधानी के तीन इलाकों का एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में रहा। अभी छह दिन तक इस स्थिति में बदलाव के आसार भी नहीं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 352 रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यानी रविवार को यह 334 रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 18 अंकों का इजाफा देखा गया। रोहिणी, जहांगीरपुरी एवं वजीरपुर का एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज हुआ। एनसीआर के शहरों का एक्यूआई भी एक दिन पहले की तुलना में बढ़ा हुआ देखा गया।

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले छह दिनों के दौरान हवा की रफ्तार 10 किमी से नीचे ही रहेगी। मौसमी परिस्थितियां भी प्रतिकूल रहेंगी। ऐसे में एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बना रहेगा।

सोमवार को एनसीआर के शहरों का एक्यूआई

दिल्ली- 352
गुरुग्राम- 294
गाजियाबाद- 252
ग्रेटर नोएडा- 285
नोएडा- 240
फरीदाबाद- 181

सोमवार को दिल्ली के इन इलाकों की हवा रही सबसे खराब

जहांगीरपुरी- 419
रोहिणी- 405
वजीरपुर- 412

न्यूनतम तापमान सामान्य से रहा ऊपर

मौसमी उतार चढ़ाव के बीच सोमवार को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर ही रहा। यह 18 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहा। दिन में आसमान साफ रहा। दूसरी तरफ हवा मंद होने से आज दिल्ली का एक्यूआई फिर से थोड़ा बढ़कर 350 के करीब हो गया है। रविवार को यह 334 रहा था। प्रदूषण को श्रेणी अभी भी बहुत खराब ही है। सुबह 9 बजे यह 349 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की मानें तो अभी अगले कुछ दिन मौसम में बहुत अधिक बदलाव होने के आसार नहीं हैं।

जगदीश टाइटलर ने हाईकोर्ट से मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का किया अनुरोध, जानें क्या दी दलीलें

परिवहन विशेष न्यूज

जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जब तक हाईकोर्ट उनके खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर लेता तब तक निचली अदालत मामले में आगे न बढ़े।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

टाइटलर की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि मामला मंगलवार को निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध है और निचली अदालत को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जब तक हाईकोर्ट उनके खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक वह मामले में आगे न बढ़े।

टाइटलर की याचिका 29 नवंबर को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने रजिस्ट्री को दिन के दौरान दस्तावेज को रिकार्ड में रखने का निर्देश दिया। टाइटलर की याचिका, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई है, पहले ही 29 नवंबर को हाई कोर्ट में सूचीबद्ध है और इसके लंबित रहने के दौरान, टाइटलर ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की गवाह लोकेंद्र कौर का साक्ष्य निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया था और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उसकी जिरह 12 नवंबर को निर्धारित की गई है। टाइटलर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका ने अभियोजन पक्ष की मंशा और सीबीआई द्वारा की गई जांच पर पर्याप्त सवाल उठाए हैं।

चौथी बार गवाह मंगलवार को अदालत में पेश होंगी

पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने स्थगन आवेदन का विरोध किया और कहा कि गवाह वृद्ध है और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। उसे कई बार निचली अदालत में पेश होना पड़ रहा है। अधिवक्ता ने दलील दी कि चौथी बार वह मंगलवार को अदालत में पेश होंगी। टाइटलर ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह जासूसी का शिकार है और दलील दी कि उसके खिलाफ आरोप तय करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, अवैध और विवेकहीन था।

'कोई भी धर्म नहीं सिखाता प्रदूषण फैलाना', दिल्ली में पटाखे फूटने पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को फटकार

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है क्योंकि पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में विफल रही और सिर्फ केवल कच्चा माल ही जब्त किया। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री और निर्माण पर रोक सुनिश्चित करें।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, क्योंकि पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में विफल रही और सिर्फ केवल कच्चा माल ही जब्त किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का सभी का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है, कोई भी धर्म ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो।

पटाखों की बिक्री और निर्माण पर हो रोक

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री और निर्माण पर रोक सुनिश्चित करें। कोर्ट ने सभी पक्षों को तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया है।

पटाखों पर प्रतिबंध के काम पूरी तरह से हों

कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को एक स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया है, जो सनिश्चित करे कि पटाखों पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन पूरी तरह से हों। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंध लागू करने लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर दर्ज करने के लिए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों हुई?

कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबध लगाने में 14 अक्टूबर तक की देरी क्यों की, जबकि प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था।

पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर करें काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार हितधारकों का पक्ष लेकर 25 नवंबर से पहले पटाखों पर पूरी तरह से यानी 'स्थायी' प्रतिबंध लगाने का फैसला करे।

दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज यानी सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान एक्यूआई (AQI) बेहद खराब स्थिति में रहा। उधर, आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी दर्ज की गई। आइए आपको बताते हैं कि कहां कितना एक्यूआई दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कई क्षेत्रों में 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिससे इंडिया गेट और विजय चौक के आसपास के क्षेत्र में धुंध की मोटी परत छाई हुई है।

दिल्ली के इलाकों का एक्यूआई

आनंद विहार में सुबह आठ बजे एक्यूआई 382 दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 380 रहा, जबकि बवाना में 401 दर्ज किया गया है। उधर, आईजीआई एयरपोर्ट पर 337 दर्ज किया गया। वहीं, जहांगीरपुरी में और खराब स्थिति देखने को मिली। यहां पर एक्यूआई 411 दर्ज किया गया है। एनएसआईटी द्वारिका में 381 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग में 389 AQI दर्ज किया गया है।

जल्द आएगा डूसु चुनाव का रिजल्ट, दिल्ली HC ने दी मतगणना शुरू करने की इजाजत

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के मतों की गिनती शुरू करने का निर्देश दिया है। 26 नवंबर या उससे पहले तक मतगणना शुरू की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मतगणना से पहले चुनाव प्रचार के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों को ठीक किया जाए। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्रों को 10 दिनों में अदालत की रजिस्ट्री में रिपोर्ट देनी होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया 26 नवंबर या उससे पहले शुरू करने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा विरूपित किए गए सभी स्थलों को एक सप्ताह के भीतर साफ कर दिया जाए और फिर से पेंट किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका बंद करते हुए डीयू को निर्देश दिया कि यदि वह इस बात पर संतुष्ट है कि शेष स्थल साफ हो गए हैं तो 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना प्रक्रिया शुरू की जाए। पीठ ने कहा कि कार्यवाही का उद्देश्य छात्रों को दंडित करना नहीं बल्कि सुधार करना था। ताकि छात्र यह महसूस करें कि विश्वविद्यालय की संपत्ति जनता की है और वे सीमित अवधि के लिए इसका इस्तेमाल करने के हकदार हैं।

10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना डीयू के उम्मीदवारों और वर्तमान छात्रों की जिम्मेदारी है कि अगले बैच को अच्छी और स्वच्छ स्थिति में विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का मौका मिले। पीठ ने डीयू को छात्रों द्वारा संपत्तियों की सफाई के तथ्य को सत्यापित करने और उम्मीदवारों की रिपोर्ट के साथ 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

भविष्य में ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा

मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को डीयू के अधिवक्ता ने पीठ को एक ताजा स्थिति रिपोर्ट सौंपी जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों में लगभग सभी कॉलेजों, विभागों और सुविधाओं को साफ कर दिया गया है और अब कोई विरूपण नहीं दिख रहा है। अधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में विरूपण में लिप्त लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा।

छात्रों के अधिवक्ता ने एक हफ्ते में साफ करने का दिया आश्वासन

वहीं, उम्मीदवारों द्वारा एक हलफनामा भी दायर किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि विरूपण को हटाने के लिए सफाई अभियान में भाग लेकर परिसरों को बहाल करने के लिए कदम उठाए गए थे। याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने कहा कि कई कालेजों, विभागों और संकायों को साफ कर दिया गया है और विरूपण हटा दिया गया है, फिर भी परिसरों के पास स्थित सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर कई पोस्टर, भित्तिचित्र और स्प्रे पेंट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी स्थलों को साफ किया जाएगा और फिर से पेंट किया जाएगा।

व्यापक तरीक से हुई गंदगी के बाद कोर्ट ने मतगणना रोक दी थी

अदालत ने विश्वविद्यालय के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त और नष्ट किए जाने के बाद मतगणना रोक दी थी। अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने संभावित डूसू उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें गंदा करने और नष्ट करने के आरोप में कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

दिल्ली में नौकरी का आया बंपर मौका, एलजी सक्सेना ने तत्काल 1463 पदों पर भर्ती की दी मंजूरी

दिल्ली में नौकरी का बंपर मौका आनेवाला है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल स्टाफ सहित 1463 स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित समिति की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधायों को लेकर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट की भी मांग की थी।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल स्टाफ सहित 1463 स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती को मंजूरी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी और दिल्ली सरकार को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें सरकार को दिल्ली में स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को किस तरह बड़ी आबादी तक पहुंचा रही है, इसकी जानकारी भी मांगी थी।

एलजी वीके सक्सेना ने सोमवार को 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल कर्मियों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती को मंजूरी दे दी। राजनिवास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 1,463 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती का यह अभियान, अस्पतालों को भर्ती नियमों में ढील के साथ सीधी भर्ती कोटे के तहत आवश्यक कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

भर्तियां डॉ. एस के सरीन समिति की सिफारिशों पर

इसमें कहा गया है कि 'आउटसोर्स' आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय शहर के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मौजूदा चिकित्सा कर्मचारियों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह भर्ती डॉ. एस के सरीन समिति की सिफारिशों पर की जा रही है। समिति का गठन शहर में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों और कार्यबल के बारे में हाइकोर्ट द्वारा चिंता जताए जाने के बाद किया गया था।

कोर्ट ने हालिया स्वास्थ्य व्यवस्था को माना था अपर्याप्त

मालूम हो कि हाइकोर्ट ने फरवरी में जारी एक निर्देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त भी माना था।

एलजी ने अस्पतालों के बिस्तरों और कर्मियों की कमी पर दिया जोर

राजनिवास के अनुसार अदालत ने जीएनसीटीडी को यह आदेश दिया है कि वह अपनी योजनाओं पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा प्रणाली शहर की जरूरतों के साथ तालमेल रख सके। विशेष रूप से अस्पतालों के बिस्तरों और चिकित्सा कर्मियों की कमी पर जोर दिया जा सके।

स्वदेश निर्मित अग्निरोधक वर्दी से 449 डिग्री आग के तापमान में भी हो सकेगा बचाव, जानें क्या है 'कवच' की खास विशेषता

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। अग्निशमन कर्मी खुद की जान जोखिम में डालकर आग जैसी आपदा के संकट को टालते हैं। इस दौरान कई बार बड़े हादसों में ये अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इसी बड़े जोखिम को कम करने के लिए अब स्वदेशी अग्निरोधक वर्दी को तैयार किया जा रहा है। इसको 'कवच' नाम दिया गया है। इसका उपयोग 449 डिग्री के उच्च तापमान तक में भी किया जा सकेगा।

उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा) की ओर से तैयार स्वदेशी अग्निरोधी फैब्रिक से तैयार हो रहा कवच पर्यावरण के अनुकूल है और सुरक्षित भी। साथ ही अब तक विदेश से आयात किए जाने वाले फैब्रिक की तुलना में सस्ता भी।

देश में अभी तक बनाए जाने वाले अग्निरोधी फैब्रिक अधिक सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। इस नए फैब्रिक को निटरा के विज्ञानियों ने अरविंद ह्यूमन प्रोटेक्शन कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, जहां आग लगने का खतरा अधिक होता है। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से अग्निशमन कर्मी, भारी उद्योगों और जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारी कर सकेंगे। इस फैब्रिक की सुरक्षा जांच के लिए निटरा के विज्ञानियों ने एक कंपनी के साथ मिलकर करीब डेढ़ वर्ष तक शोध किया। इसमें यह पर्यावरण के अनुकूल व टिकाऊ पाया गया। यह स्वदेशी व सस्ता तो है ही।

जूट, काटन और एल्युमिनियम से तैयार किया फैब्रिक

निटरा के निदेशक एवं विज्ञानी डॉ. एमएस परमार ने सहायक विज्ञानी श्वेता सक्सेना और निधि सिसोदिया के साथ मिलकर इस फैब्रिक को तैयार किया है। इसमें एक निश्चित मात्रा में जूट और काटन के अलावा एल्यूमिनियम और कांच का प्रयोग किया है। काटन, जूट के उपयोग से तैयार होने की वजह से इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा। डॉ. एमएस परमार ने बताया कि अभी तक आयातित महंगे फाइबर से इसे तैयार किया जाता था, जिस कारण उद्योग अपने कर्मियों को इस फैब्रिक से बनी ड्रेस को देने में कंजूसी करते थे, लेकिन यह स्वदेशी अग्निरोधी ड्रेस सुरक्षित और बजट में होगी। अभी प्रयोग की जाने वाली ड्रेस सादी सूती होती है, इसलिए अधिक जोखिम भी रहता है।

पांच मिनट तक आग से कवच करेगा सुरक्षा

डॉ. परमार के मुताबिक अग्निरोधक फैब्रिक को जूट और काटन पर स्पेशल फ्लेम रेसिस्टेंस केमिकल से तैयार कर बनाया गया है जो इसको अग्निरोधी बनाता है एल्युमिनियम की शीट से जो हीट आती है, उसको रिफ्लेक्ट करने में इससे मदद मिलती है। जहां तक इसे पहनकर 449 डिग्री तक की आग में रहने की बात है तो यह फंसे लोगों को आग से निकालने वालों के लिए है, इसे पहनकर पांच मिनट तक इतनी अधिक आग में रहा जा सकता है।

आग से सुरक्षा के साथ-साथ आरामदायक भी

शोधकर्ताओं के अनुसार, नया फैब्रिक न केवल आग से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि इसके बनी ड्रेस पहनने में भी आरामदायक होगी। इसे लंबी अवधि तक उपयोग में लाया जा सकता है।

विदेशी की कीमत 15 लाख और स्वदेसी की दो लाख

निटरा के विज्ञानी डॉ. एमएस परमार ने बताया कि अग्निरोधी फैब्रिक को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाया गया है। यह सैन्य संस्थाओं के साथ ही बड़े उद्योगों के बजट में होगा। इसकी कीमत दो से ढ़ाई लाख प्रति ड्रेस के आसपास हो सकती है, जबकि विदेशी अग्निरोधी ड्रेस की कीमत करीब 13 से 15 लाख रुपये होती है। हां, जब अधिक उत्पादन होने लगेगा तो दो-ढाई लाख से भी कम हो सकती

"अभी अग्निशमन विभाग के पास आग से बचाव के लिए इस स्तर के संसाधन नहीं है। अभी सूती कपड़ों के अलावा एक-दो सूट ऐसे हैं, जो 35 से 70 डिग्री तक आग से बचाव में काम करते हैं। अगर 100 से 449 डिग्री तक तापमान से बचाव के लिए सूट स्वदेशी मिलेंगे तो इसका लाभ अग्निशमन विभाग को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। - राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद "

"अग्निरोधी फैब्रिक लुधियाना की स्टील फैक्ट्री में इसका ट्रायल हो चुका है इस शोध को पूरा होने में करीब डेढ़ साल का समय लगा है। इसके लिए कंपनी जल्द ही बजट में सैन्य एजेंसियों और उद्योगों के लिए इसका निर्माण बड़े स्तर पर आरंभ करेगी। - डॉ. अरिंदम बसु, महानिदेशक, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ"

वसुंधरा के फ्लैट में देह व्यापार, पुलिस ने छापा मारकर दिल्ली की तीन लड़कियों को किया बरामद

वसुंधरा सेक्टर-1 में पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने प्रबंधक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया है। मौके से आपत्तिजनक सामान चार मोबाइल चेकबुक और पासबुक बरामद की गई हैं। चार महीने से यहां देह व्यापार का धंधा चल रहा था।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली के वसुंधरा सेक्टर-1 में पुलिस ने फ्लैट में चल रहे देह व्यापार (Deh Vyapar) का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने प्रबंधक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीन महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया है।

पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान, चार मोबाइल, चेकबुक, पासबुक बरामद की हैं। चार माह से यहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था।

प्रबंधक और दो ग्राहक दबोचे

पुलिस को रविवार को सूचना मिली थी कि वसुंधरा सेक्टर-एक के मकान नंबर 61 में देह व्यापार (Flesh Trade) हो रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ मौके पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से प्रबंधक और दो ग्राहकों को दबोच लिया। तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया गया।

ये हैं गिरफ्तार आरोपी

मौके से चार मोबाइल, चेकबुक, पासबुक और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पुलिस (Ghaziabad Police) सभी को कोतवाली ले आई। पकड़े गए आरोपी प्रबंधक ग्राम सुराना मुरादनगर का रोहित कुमार, ग्राम प्रह्लादगढ़ी का प्रिंस भारती, वसुंधरा सेक्टर-9 के राजेंद्र गोंडाने हैं। जबकि फ्लैट मालिक एवं संचालक पसौंडा टीला मोड़ का रविंद्र कुमार फरार हैं।

दिल्ली की हैं युवतियां, नौकरी का दिया झांसा

पुलिस पूछताछ में रेस्क्यू की गई महिलाओं ने बताया कि वह सभी दिल्ली की हैं। नौकरी का झांसा देकर उन्हें यहां बुलाया गया। बहला फुसलाकर उनसे गलत काम कराया गया। विरोध किया तो उनके आपत्तिजनक वीडियो व फोटो प्रसारित करने की धमकी दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम की ओर से सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

चार माह से चल रहे था फ्लैट में

पुलिस जांच में सामने आया है कि चार माह से यहां पर फ्लैट में देह व्यापार चल रहा था। संचालक रविन्द्र कुमार व उनके प्रबंधक रोहित ज्यादा कमाई के लालच में रेस्क्यू की गई महिलाओं से देह व्यापार कराकर ग्राहकों से रुपये लेते थे। एक ग्राहक से एक हजार रुपये लिए जाते थे।

पांच सौ रुपये महिलाओं को देते थे। पकड़ा गया प्रबंधक साहिबाबाद कोतवाली से देह व्यापार में जेल जा चुका है। करीब 15 दिन छूट कर बाहर आ गया था। उसके बाद से फिर देह व्यापार करने लगा।

हाल में हुई कार्रवाई

- नौ नवंबर को विजयनगर के दो होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश। संचालक, प्रबंधक समेत छह गिरफ्तार।
- आठ नवंबर को तुलसी निकेतन पुलिस चौकी के पीछे गली के दो फ्लैटों में देह व्यापार का पर्दाफाश। संचालिका समेत दो गिरफ्तार।
- दो नवंबर को शालीमार गार्डन एक्सटेंशन दो में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर के बेटे के फ्लैट में देह व्यापार का पर्दाफाश। संचालिका समेत तीन गिरफ्तार
- 26 सितंबर 2024 को कोतवाली क्षेत्र के बजरिया के पांच होटलों में हो रहा था देह व्यापार। आठ जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे।
- 27 अगस्त को साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एजी पीजी हॉस्टल में चल रहा था देह व्यापार। संचालिका समेत चार गिरफ्तार
- पांच अगस्त को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के डीएलएफ कालोनी स्थित फ्लैट में देह व्यापार का पर्दाफाश संचालिका समेत पांच गिरफ्तार

भूमाफियाओं ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दोबारा बेच दी बेची गई जमीन, फर्जी दस्तावेज बनाकर लगाया चूना

ग्रेटर नोएडा में जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्राधिकरण को बेची गई जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर वही जमीन दोबारा प्राधिकरण को बेच दी। पीड़ित खरीदार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आए दिन जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी भनौता गांव का है, जहां आरोपियों ने प्राधिकरण (Greater Noida Authority) को बेची गई जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर वह जमीन दोबारा प्राधिकरण को बेच दी।

अब पीड़ित खरीदार ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वैदपुरा गांव के नरेंद्र कुमार का आरोप है कि उन्होंने भनौता गांव में उन्होंने 0.960 हे. एक भूखंड खरीदा था।

16 लाख में हुआ सौदा

16 लाख 32 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। जिसका दाखिल खारिज भी उनके पक्ष में हो गया। इसके बाद आरोपियों से एक अन्य भूखंड का सौंदा 40 लाख रुपये में हुआ, जिसका वे आरोपियों को साढ़े 35 लाख रुपये का नकद व उनके बैंक खातों में भुगतान कर चुके हैं।

बैनामा में कर रहा था आनाकानी

आरोप है कि जब बैनामा करने की बात आई तो आरोपी आनाकानी कराने लगे। जब उन्होंने जमीन के बाबत जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि 0.960 हे. जमीन का बैनामा आरोपी 2015 में ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Authority Land) के पक्ष में कर चुके हैं।

रकम हड़पने के लिए रची साजिश

पीड़ित का दावा है कि उनकी रकम हड़पने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें जमीन बेची गई। आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने खेड़ी भनौता गांव के अन्तराम, प्रमोद, मनोज, विनोद, संजय, राकेश संदीप व ब्रोकर संजीव शर्मा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है हैप्पी कार्ड स्कीम? लोगों में हो रही है लोकप्रिय; जिले के 6 हजार से ज्यादा लोग उठा रहे हैं लाभ

गुरुग्राम। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड) का जिले के 6,274 लोग लाभ उठा रहे हैं। जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है, वह हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

कार्ड बांटने में लगी हैं पांच टीमें

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि योजना के अनुसार, हैप्पी कार्ड धारक नागरिक रोडवेज की बसों में हर साल एक हजार किलोमीटर तक निःशुल्क सफर कर सकता है। कार्ड का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। एटीएम की तरह नीले रंग का दिखाई देने वाला हैप्पी कार्ड बांटने के लिए परिवहन विभाग ने पांच टीमें बनाई हुई हैं जो कि गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी व फरुखनगर में काम कर रही हैं।

8,789 लोगों ने किया आवेदन

कार्ड बनवाने के लिए 8,789 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इनमें से 6,274 को कार्ड दिया जा चुका है और 2505 कार्ड दिए जाने बाकी रह गए हैं। जनसेवा पोर्टल के माध्यम से इस कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद रोडवेज विभाग में जाकर यह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

50 रुपये लिया जाता है शुल्क

परिवहन विभाग की ओर से एक ओटीपी नंबर आवेदक के मोबाइल पर भेजा जाता है। ओटीपी नंबर डालते ही आवेदक का हैप्पी कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। हर कार्ड पर 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024-संकल्प पत्र बनाम महाराष्ट्रनामा

महाराष्ट्र में महायुती व महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्रों में जनता के लिए वादों की बरसात!

महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर दोनों पक्षों के शाब्दिक बाणों के बाउंसर के बीच 17 मांगों वाली चिट्ठी की पोलखोल,अब घोषणापत्रों की बोलाबोल –एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा एक ऐसा लोकतंत्र है,जहां करीब करीब वर्ष भर चुनावी महापर्व लगा रहता है, चाहे लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर उपचुनाव जिसमें भारी आर्थिक लागत के बीच आचार संहिता भी ! कुल मिलाकर बोझ जनता पर ही पड़ता है, इसीलिए भारत सरकार को कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव एक भारत एक चुनाव को लागू करना समय की मांग है। अभी झारखंड में दो चरणों 13 व 20 तथा महाराष्ट्र में एक चरण 20 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव है जिसमें झारखंड में 11 नवंबर 2024 को शाम चुनाव प्रचार थम गया है, परंतु महाराष्ट्र में चुनावी शाब्दिक बाणों की जंग बहुत तेजी से जोरदार तरीके से बढ़ती जा रही है ।पीएम से लेकर प्रदेशों केसीएम व गृहमंत्री के धड़ाधड़ दौर चालू हैं। मेरी पूरी नज़र मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र चुनाव पर लगी हुई है। एक ओर जहां यूपी सीएम व पीएम के नारों, बाटोगे तो कटोगे एक है तो नेक हैं,नें डेरा जमाए हुए हैं, तो दूसरी ओर उलेमा संगठन द्वारा लिखी 17 मांगों वाली चिट्ठी ने भी खलबली मचा दी है, तो वहीं यूपी सीएम पर वस्त्रास्त्र के बांण चलाए जा रहे हैं,तो ऐसा लग रहा है,मानों पूरे भारत के शाब्दिक बांण महाराष्ट्र में छोड़े गए हैं। हर पार्टी क़े शीर्ष नेता महाराष्ट्र दौरे पर है, मानो महाराष्ट्र जीता तो विश्व जीतें ।रविवार दिनांक 10 नवंबर 2024 का दिन जनता के ऊपर चुनावी वादों की बारिश का रहा, जिसपर दिन भर मेरी पूरी नज़र रही। महायुतीयांने भाजपा व महा आघाड़ी द्वारा घोषित चुनावी घोषणा पत्रों पर देर शाम से हो रही सोशल मीडिया व टीवी चैनलों पर डिबेट जो देररात तक होती रही, जिससे 17 मागों वाला चिट्ठी का मुद्दा दब गया और देररात तक मैं इस विषयपर रिसर्च कर यह आर्टिकल तैयार किया ।चूँकि महाराष्ट्र में महायुती व महाआघाड़ी के घोषणा पत्रों में जनता के लिए वादों की बरसात की गई इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकलके माध्यमसे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024-संकल्पपत्र बनाम महाराष्ट्रनामा।

साथियों बात अगर हम 10 नवंबर 2024 को महायुती (भाजपा) व महाविकास आघाड़ी द्वारा जारी घोषणा पत्रों की करें तो,एमवीए और सत्तारूढ़ महायुति ने रविवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने घोषणापत्र जारी कर दिए ।घोषणापत्र सार्वजनिक किए जाने के समय दोनों गठबंधनों के दिग्गज नेता मौजूद रहे ।महायुति का घोषणापत्र केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एमवीए घोषणापत्र जारी किया ।दोनों घोषणापत्रों में महाराष्ट्र के समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने की कोशिश की गई है ।सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है,महायुति ने 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी किया है ।इसके अलावा गठबंधन ने रिवॉल्विंग फंड में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का वादा किया है ।वहीं,एमवीए ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का भी वादा किया है ।महायुति ने राज्य के किसानों से 15 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया हैसत्तारूढ़ गठबंधन ने कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी वादा किया है ।इसने बिजली बिलों में कमी का भी वादा किया है ।दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने समय पर अपना कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हज़ार रुपये देने का वादा किया है ।महायुति ने10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये का वजीफा देने का वादा किया गया है। महायुति ने कहा है कि वह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनाएगी ।इसके अलावा महायुति ने राज्य में कौशल जनगणना कराने का भी वादा किया है ।उधर, एमवीए ने राज्य के हर एक छात्र को 4000 रुपये वजीफा देने की घोषणा करके युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है ।राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन ने कहा है कि वह विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी और युवाओं के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करेगी ।महायुति ने कहा है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आधार एनेबल सर्विस नीति शुरू करेगी, साथ ही उनके लिए डेडिकेटेड आउट-पेशेंट विभाग भी चलाएगी,वहीं, एमवीए ने राज्य में 25 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का वादा किया है ।कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह योजना राजस्थान के पूर्व सीएम द्वारा अपने राज्य में शुरू की गई योजना के समान होगी ।गठबंधन ने मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने का भी वादा किया ।महायुति ने कहा कि वह वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन को 21,500 रुपये से बढ़ाकर 82,100 रुपये करेगी, जबकि एमवीए ने बुजुर्गों को पेंशन के मामले को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया है ।सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना का उल्लेख नहीं किया है और न ही इसके बारे में कोई वादा किया है, हालांकि, महायुति ने कहा है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 15 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगी ।वहीं, एमवीए ने घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वह राज्य में जाति जनगणना कराएगी और आरक्षण पर 50प्रतिशत की सीमा भी हटा देगी।

साथियों बात अगर हम भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाओं की करें तोबीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें (1) लाडली बहनों को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा 25000 महिलाओं को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा(2) किसानों की कर्जमाफी दी जाएगी (3) हर गरीब को भोजन और आश्रय दिया जाएगा (4) वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपये दिए जाएंगे (5) महाराष्ट्र के सभी परिवारों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी (6) आने वाले समय में 25 लाख रोजगार सृजन और 10 लाख विद्यार्थियों को प्रति माह 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा (7) राज्य के ग्रामीण इलाकों के 45,000 गांवों में पंधान स्टेशन स्थापित किए जाएंगे (8) वित्तीय सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपये का वेतन और बीमा कवर प्रदान किया जाएगा (9) बिजली बिलों में 30% की कमी कर सौर और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा (10) सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र@2029 पेश किया जाएगा (12) महाराष्ट्र को प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे (13) व्यापक गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।(14) वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी तैयार की जाएगी (15) अक्षय अन्न योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा. जिसमें चावल, ज्वार, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च पाउडर शामिल होगा (16)सभी सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स और एआई सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए मराठी- अटल टिंकरिंग लैब्स योजना शुरू की जाएगी (17) उद्योग की जरूरतों के अनुसार कौशल की कमी का विश्लेषण करने और उसके आधार पर उपलब्ध कुशल जनशक्ति प्रदान करने और आवश्यकतानुसार नई कुशल जनशक्ति की योजना बनाने के लिए महाराष्ट्र में एक कौशल जनगणना आयोजित की जाएगी (18) महाराष्ट्र के हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से 10 लाख नए उद्यमी तैयार किए जाएंगे (19) अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को व्यवसाय वृद्धि के लिए 115 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋृण उपलब्ध कराया जाएगा (20) ओबीसी, एसईबीसी ईडब्ल्यूएस, एनटी, वीजेएनटी के योग्य छात्रों को ट्यूशन शुल्क और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी (21)18 से 35 वर्ष के युवाओं की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य आरोग्य कार्ड (वुथ हेल्थ कार्ड) (22) लॉन्च किया जाएगा और नशा मुक्त महाराष्ट्र के लिए स्थायी योजना लागू की जाएगी (23) वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता' सिद्धांत को अपनाया जाएगा (24) जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा (25) बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, जंगली सूअर और बंदर जैसे जंगली जानवरों से होने वाली जान-माल की हानि को रोकने के लिए एआई तकनीक और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024-संकल्प पत्र बनाम महाराष्ट्रनामा ।महाराष्ट्र में महायुती व महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्रों में जनता के लिए वादों की बरसात !महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर दोनों पक्षों के शाब्दिक बाणों के बाउंसर के बीच 17मांगों वाली चिट्ठी की पोलखोलअब घोषणापत्रों की बोलाबोल।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

किआ इंडिया ने अपनी शानदार किआ 2.0 एसयूवी का नाम 'SYROS' रखने की घोषणा की

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। किआ इंडिया एक प्रमुख प्रीमियम कार निर्माता ने सोमवार, दिनांक 11 नवंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित किआ 2.0 एसयूवी का नाम घोषित किया, जिसका नाम किआ SYROS हैं। एक शानदार वाहन जो नए युग के शानदार बोल्ड डिज़ाइन, उन्नत तकनीक और पौराणिक विरासत का सही मिश्रण है। SYROS, कार्निवल और ईवी 9 के बाद किआ की पहली 2.0 एसयूवी होगी। यह किआ की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करेगी, जो परंपरा को नवाचार के साथ मिलाएगी। यह नामकरण रणनीति किआ की उन वाहनों को बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है जो भावनात्मक स्तर पर ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं।

SYROS एक एसयूवी की व्यावहारिकता को एक विशिष्ट, बोल्ड डिज़ाइन, अत्याधुनिक तकनीक और शीर्ष-स्तरीय सुरक्षा के साथ सहजता से मिश्रित करता है। इसकी प्रगतिशील स्टाइलिंग पारंपरिक एसयूवी मानदंडों को चुनौती देती है, जो एक ताज़ा और रोमांचक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है। अभिनव सुविधाओं, असाधारण प्रदर्शन और बेजोड़ आराम से भरपूर, SYROS अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित करने और अपने सेगमेंट में मानक बढ़ाने के लिए तैयार है। आधुनिक, तकनीक-प्रेमी खरीदार के लिए डिज़ाइन किया गया, केबिन एक अल्ट्रा-विशाल वातावरण प्रदान करता है, जो वास्तव में अगली पीढ़ी के ड्राइविंग अनुभव के लिए उद्योग-प्रथम कनेक्टेड सुविधाओं से परिपूर्ण है।

फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी बेड़े में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन किए शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी बेड़े में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन जोड़े हैं। ई-कॉमर्स कंपनी ने 13 नवंबर को राजधानी नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में होने वाले अपने सस्टेनेबिलिटी एक्शन समिट 2024 से पहले यह जानकारी दी है।

सोमवार, 11 नवंबर को जारी बयान में फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने अपने डिलीवरी बेड़े में 10 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए हैं, जो एक मील का पत्थर है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले कुछ वर्षों में अंतिम मील डिलीवरी में ईवी के चरणबद्ध एकीकरण का परिणाम है, जो क्लाइमेट ग्रुप की ईवी 100 पहल के हिस्से के रूप में 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स लास्ट-माइल बेड़े को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

वर्तमान में फ्लिपकार्ट के इलेक्ट्रिक बेड़े का 75% हिस्सा दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई सहित टियर-1 शहरों में केंद्रित है। फ्लिपकार्ट के अनुसार अगस्त 2024 से उसके 55% से अधिक किराना ऑर्डर ईवी के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2024 के त्योहारी सीजन में कंपनी ने लखनऊ, सोनीपत, लुधियाना, भुवनेश्वर, मालदा, हुबली और विजाग सहित टियर-2+ शहरों में 16% से अधिक किराना डिलीवरी को पूरा करने के लिए अपने ईवी बेड़े का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है, जिससे उच्च मांग वाले मौसम के दौरान इन क्षेत्रों में टिकाऊ और कुशल सेवा सुनिश्चित हुई है।

कंपनी ने कहा कि ईवी को रणनीतिक रूप से अपनाने से इसकी परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हब स्तर पर प्रति ऑर्डर लागत में कमी आई है और पारंपरिक डिलीवरी वाहनों की तुलना में अंतिम मील डिलीवरी की गति में 20 प्रतिशत सुधार हुआ है। अपने ईवी बेड़े का विस्तार करने के अलावा फ्लिपकार्ट ने इस स्थायी बदलाव का समर्थन करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसने प्रमुख टियर-2 शहरों में कुल 190 चार्जर के साथ 38 समर्पित चार्जिंग साइट स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ साझेदारी की है।

फ्लिपकार्ट ने कहा कि वह ईवी की सुविधा के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा कंपनी ने कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लास्ट-माइल एग्रीगेटर मॉडल पेश किया है, जो आपूर्ति श्रृंखला संचालन को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के एकीकरण को बढ़ाने के लिए ईवी-केंद्रित बेड़े ऑपरेटरों के साथ सहयोग कर रहा है।

फ्लिपकार्ट में ग्रुप हेड, सप्लाई चेन, कस्टमर एक्सपीरियंस और ई-कॉमर्स बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमंत बद्री ने कहा कि 10 हजार से ज्यादा ईवी की तैनाती के साथ, हमने जो हासिल किया है, वह लॉजिस्टिक्स बदलाव से कहीं ज्यादा है।

आरटीओ विभाग ने अंतिम सत्यापन के लिए दिया मौका ऑटो चालकों को

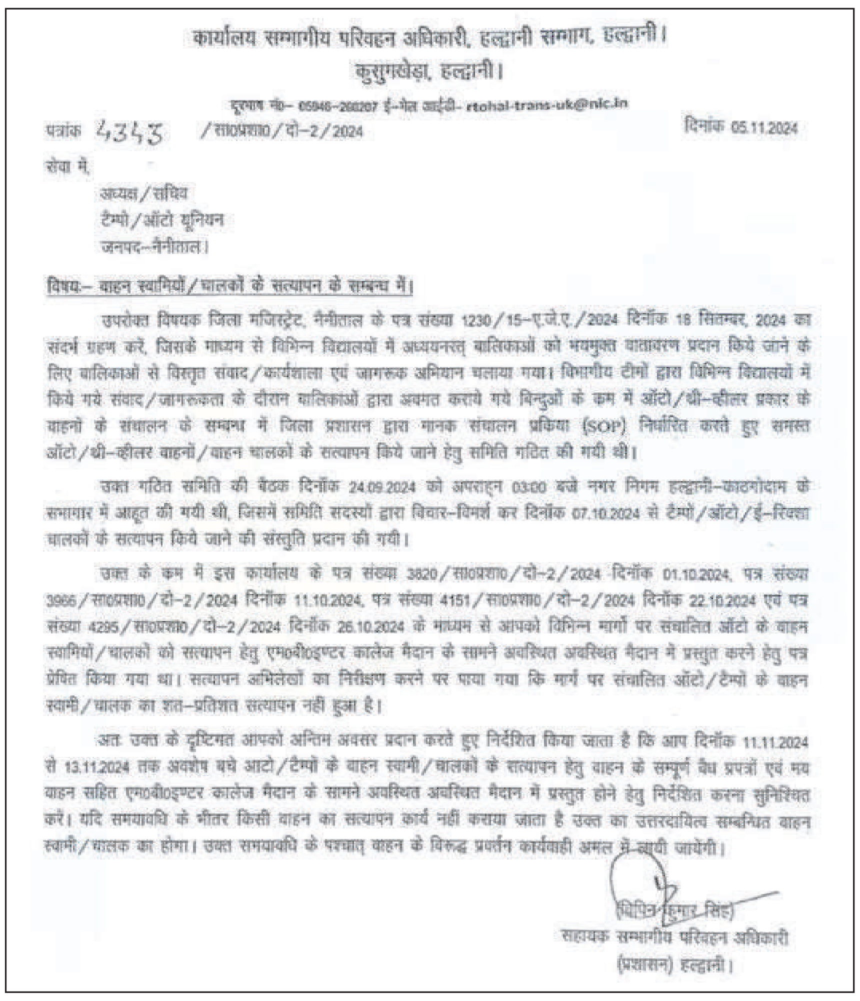

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, हल्द्वानी।
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।
दूरभाष नं०- 05946-288207 ई-मेल आईडी- rtohal-trans-uk@nic.in

पत्रांक 4353 /सा०प्रशा०/दो-2/2024 दिनांक 05.11.2024

सेवा में,
अध्यक्ष/सचिव
टैम्पो/ऑटो यूनियन
जनपद-नैनीताल।

विषय- वाहन स्वामियों/चालकों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पत्र संख्या 1230/15-ए.जे.ए./2024 दिनॉक 18 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान किये जाने के लिए बालिकाओं से विस्तृत संवाद/कार्यशाला एवं जागरूक अभियान चलाया गया। विभागीय टीमों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में किये गये संवाद/जागरूकता के दौरान बालिकाओं द्वारा अवगत कराये गये बिन्दुओं के क्रम में ऑटो/थ्री-व्हीलर प्रकार के वाहनो के संचालन के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करते हुए समस्त ऑटो/थ्री-व्हीलर वाहनों/वाहन चालकों के सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी थी।

उक्त गठित समिति की बैठक दिनॉक 24.09.2024 को अपराह्न 03:00 बजे नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के सभागार में आहूत की गयी थी, जिसमें समिति सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर दिनॉक 07.10.2024 से टैम्पो/ऑटो/ई-रिक्शा चालकों के सत्यापन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 3820/सा०प्रशा०/दो-2/2024 दिनॉक 01.10.2024, पत्र संख्या 3966/सा०प्रशा०/दो-2/2024 दिनॉक 11.10.2024, पत्र संख्या 4151/सा०प्रशा०/दो-2/2024 दिनॉक 22.10.2024 एवं पत्र संख्या 4295/सा०प्रशा०/दो-2/2024 दिनॉक 26.10.2024 के माध्यम से आपको विभिन्न मार्गो पर संचालित ऑटो के वाहन स्वामियों/चालकों को सत्यापन हेतु एम०बी०इण्टर कालेज मैदान के सामने अवस्थित अवस्थित मैदान में प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। सत्यापन अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मार्ग पर संचालित ऑटो/टैम्पो के वाहन स्वामी/चालक का शत-प्रतिशत सत्यापन नहीं हुआ है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप दिनॉक 11.11.2024 से 13.11.2024 तक अवशेष बचे आटो/टैम्पो के वाहन स्वामी/चालकों के सत्यापन हेतु वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित एम०बी०इण्टर कालेज मैदान के सामने अवस्थित अवस्थित मैदान में प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यदि समयावधि के भीतर किसी वाहन का सत्यापन कार्य नहीं कराया जाता है उक्त का उत्तरदायित्व सम्बन्धित वाहन स्वामी/चालक का होगा। उक्त समयावधि के पश्चात् वाहन के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(विपिन कुमार सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) हल्द्वानी।

परिवहन विशेष न्यूज

हल्द्वानी आरटीओ विभाग ने ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों में ऑटो/थ्री व्हीलर वाहनों के संचालन से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी ऑटो/थ्री व्हीलर वाहनों/चालकों के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई है और एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 अक्टूबर 2024 से टेंपो, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने संबंधित वाहन स्वामियों/चालकों को कई बार सूचित किया कि वे सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों और वाहन के साथ एमबी इंटर कॉलेज के सामने मैदान में उपस्थित हों। अभी तक सभी वाहनों का सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है।

इसलिए विभाग ने अंतिम मौका देते हुए निर्देश दिए हैं कि 11 से 13 नवंबर 2024 तक शेष वाहन स्वामी/चालक अपने वैध दस्तावेजों के साथ मैदान में उपस्थित होकर सत्यापन पूरा करें। यदि निर्धारित समयावधि में सत्यापन नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित वाहन स्वामी/चालक स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा तत्पश्चात उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

पीएचएफ लीजिंग ने क्रेडिफिन के रूप में की पुनः ब्रांडिंग

CREDIFIN

परिवहन विशेष न्यूज

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पीएचएफ लीजिंग लिमिटेड ने तुरंत प्रभाव से क्रेडिफिन लिमिटेड के रूप में अपनी रीब्रांडिंग की घोषणा की है। कंपनी ने भारत भर में अपने बढ़ते ग्राहक आधार को बेहतर ढंग से सेवा देने के लिए अपना कॉर्पोरेट मुख्यालय भी दिल्ली-एनसीआर में स्थानांतरित कर दिया है। नया नाम क्रेडिफिन ऋण पेशकशों की एक व्यापक श्रृंखला को दर्शाता है और यह कंपनी के लक्ष्य के अनुरूप है, जो देश भर में सुलभ वित्तीय समाधान प्रदान करना है, जो प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित है। नाम परिवर्तन के साथ, क्रेडिफिन ने एक नया लोगो लॉन्च किया है।

1998 में स्थापित और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत क्रेडिफिन पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बंधक ऋण, संपत्ति के विरुद्ध ऋण (एलएपी), एमएसएमई व्यवसाय ऋण और ई-रिक्शा, ई-लोडर और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तपोषण में माहिर है। कंपनी लॉजिस्टिक्स और परिवहन जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन करने पर केंद्रित है। क्रेडिफिन की सीईओ शल्या गुप्ता ने कहा, "क्रेडिफिन में यह परिवर्तन भारत भर में वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करने के हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमारा नया नाम विकास और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि हम ग्राहक-केंद्रितता, पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और स्थिरता के अपने मूल मूल्यों को बनाए रखना जारी रखेंगे।"

क्रेडिफिन के मुख्यालय को दिल्ली-एनसीआर में स्थानांतरित करने से कंपनी भारत के वित्तीय केंद्र के केंद्र में आ जाएगी। वर्तमान में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा प्रदान करने वाली यह नई जगह परिचालन दक्षता में सुधार करेगी और राष्ट्रीय बाजार के लिए नए वित्तीय उत्पादों के विकास में सहायता करेगी। गुप्ता ने आगे बताया, "क्रेडिफिन इस विचार पर बना है कि हम पहले इंसान हैं और फिर तकनीक। हमारा लक्ष्य अपने लोन ग्राहकों को सिर्फ़ लोन की अवधि के दौरान ही नहीं बल्कि उनकी रोज़मर्रा की वित्तीय ज़रूरतों में भी मदद करना है, जिसमें स्कूल फीस फाइनेंस, फ़ेस्टिवल लोन, इस्तेमाल किए गए मोबाइल लोन और वाटर प्यूरीफ़ायर, गीज़र और टीवी जैसे छोटे उपभोक्ता टिकाऊ सामान के लिए लोन सहित कई तरह के वित्तीय उत्पाद शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा कि नया नाम और लोगो कंपनी के जुड़ाव पर फ़ोकस और "भारत निर्माण" में इसकी भूमिका को दर्शाता है। लोगो में रुपये का प्रतीक भारतीय बाज़ार के साथ कंपनी के संबंधों को दर्शाता है, जबकि ऊपर की ओर तीर ग्राहक विकास का समर्थन करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्वांटम एनर्जी ने श्रीकाकुलम में नए ईवी शोरूम के साथ भारत में अपनी उपस्थिति का किया विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप क्वांटम एनर्जी ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक नया शोरूम खोला है। उद्घाटन में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किनिजारपु राममोहन नायडू के साथ-साथ क्वांटम एनर्जी के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। डीलरशिप नाम एचके एजेंसीज के तहत संचालित इस शोरूम का उद्देश्य क्षेत्र के ग्राहकों के लिए क्वांटम एनर्जी की इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज को देखने और उनकी विशेषताओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान बनाना है। श्रीकाकुलम शोरूम में क्वांटम एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की विविधता उपलब्ध है, जिनमें प्लाज्मा, मिलान और बिज़नेस मॉडल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को भारत में विभिन्न आवागमन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

प्लाज्मा मॉडल 1500 वॉट की मोटर से लैस है, जिसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह पूरी बैटरी चार्ज होने पर 110 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। प्लाज्मा एक्सआर वेरिएंट, जिसमें 1500 वॉट की मोटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति है, 110 किलोमीटर तक की समान रेंज प्रदान करता है।

मिलान स्कूटर में 1000 वॉट की मोटर लगी है, जिसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक की रेंज देता है। 1200 वॉट की मोटर वाले Bziness X मॉडल की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है।

क्वांटम एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक चक्रवर्ती चुक्कापल्ली ने नए स्टोर के उद्घाटन पर टिप्पणी करते हुए कहा ₹हम अपने श्रीकाकुलम स्टोर के साथ आंध्र प्रदेश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके प्रसन्न हैं, खासकर राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में बढ़ती रुचि को देखते हुए। हमारा लक्ष्य अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचाना है, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता विकल्पों की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त शोरूम स्थापित करने की योजनाएँ चल रही हैं।"

ऑटोमोटिव क्षेत्र में 50 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले संगठन कुसलवा समूह द्वारा समर्थित क्वांटम एनर्जी का लक्ष्य भारत में स्थायी गतिशीलता में योगदान करना है। श्रीकाकुलम शोरूम के उद्घाटन के साथ कंपनी अब देश भर में 69 शोरूम संचालित करती है, जो देश भर में हरित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाती है।

ओला इलेक्ट्रिक 2025 की दूसरी छमाही में पहली इलेक्ट्रिक 3व्हीलर कर सकती है लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के पोर्टफोलियो पर काम कर रही है, अगले साल की दूसरी छमाही में पहला मॉडल लॉन्च करने की संभावना है, इसके बाद 2026 में दूसरा मॉडल लॉन्च किया जाएगा।

ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भाविश अग्रवाल ने कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद निवेशकों से कहा, "हम तिपहिया वाहनों पर काम कर रहे हैं।"

हालांकि उन्होंने लॉन्च के समय का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कंपनी की प्रस्तुति से पता चलता है कि अगले साल की दूसरी छमाही के लिए एक यात्री थ्री-व्हीलर की योजना बनाई जा रही है, जबकि 2026 की दूसरी छमाही के लिए एक कार्गो थ्री-व्हीलर की योजना बनाई गई है।

अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के बारे में कहा, ₹खूबसूरती यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी आर्किटेक्चर और पावरट्रेन के मामले में यह हमारे एस1 के समान ही प्लेटफॉर्म पर बना है। केवल मैकेनिकल्स अलग हैं।"

भारत में तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बेचे गए तिपहिया वाहनों में से लगभग 54% इलेक्ट्रिक थे। इस बाजार में एमएंडएम और बजाज ऑटो प्रमुख खिलाड़ी हैं।

ओला इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में करीब 30% हिस्सेदारी है। कंपनी का लक्ष्य मार्च तक वितरण नेटवर्क को 2,000 स्टोर तक बढ़ाना है, जो अभी 782 है।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की योजना ऐसे समय में बनाई गई है जब कंपनी अगले दो सालों में 20 से ज़्यादा उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें हर तिमाही में कम से कम एक उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। इसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल और थ्री-व्हीलर शामिल हैं।

उम्मीद है कि कंपनी चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही से अपनी रोडस्टर श्रृंखला की डिलीवरी के साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्षेत्र में पदार्पण करेगी।

इस बीच, ऑटोमेकर ने अपने मॉडलों के लिए नए जनरेशन 3 प्लैटफ़ॉर्म के इस्तेमाल को पहले से तय अगस्त से अगले साल जनवरी तक टाल दिया है। इसके स्कूटर अब जनरेशन 2 प्लैटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं।

जनरेशन 3 मॉडल में चेसिस के भीतर एक एकीकृत बैटरी, चुंबक रहित मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होंगे। मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में इस प्लेटफ़ॉर्म से प्रदर्शन में 26% सुधार और लागत में 20% से अधिक की कमी आने की उम्मीद है।

बुढ़ापे में मुक्ति का रास्ता किताबों से होकर जाता है

विजय गर्ग

जब भी हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो यह नए विचारों, संभावनाओं और संस्कृतियों के ज्ञान का रास्ता खोलती है। यह उद्धरण वेरा नाज़ेरियन का है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जो हमें जीवन भर एक शिक्षक की तरह सिखाती हैं। एक मां की तरह वह हर मुश्किल में हमारा साथ देती है और एक पिता की तरह वह हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी लेती है।

जब भी हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो यह नए विचारों, संभावनाओं और संस्कृतियों के ज्ञान का रास्ता खोलती है। यह उद्धरण वेरा नाज़ेरियन का है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जो हमें जीवन भर एक शिक्षक की तरह सिखाती हैं। एक मां की तरह वह हर मुश्किल में हमारा साथ देती है और एक पिता की तरह वह हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी लेती है। वस्तुतः यह उन्हीं से प्राप्त ज्ञान हैजीवन हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हमें बेहतर बनाता है। कभी-कभी कई रिश्ते हमें भटका देते हैं, लेकिन किताबों का रिश्ता ही होता है जो हमें सही रास्ता दिखाकर मुश्किल वक्त में मदद करता है। किताबें हमारे दुख, दर्द, सुख और अकेलेपन की साथी होती हैं। इतना ही नहीं, वे ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम उन महान हस्तियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं, जो...हम अपना आदर्श मानते हैं. कभी-कभी जीवन इतना नीरस हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है। ऐसे में हम उन लोगों को जानते हैं और उनके नक्शेकदम पर चलने की प्रेरणा इन किताबों से लेते हैं। किताबें न सिर्फ हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं बल्कि हमें मानसिक समस्याओं से भी बचाती हैं। पढ़ना मस्तिष्क के लिए अच्छा व्यायाम है। पढ़ाई करते समय हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में अपना लक्ष्य हासिल करना सीखते हैं।

यहहमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। यदि हम अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें तो हम अपनी याददाश्त में कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। यह कमजोरी या अवसाद को रोकने के उपचार के रूप में प्रभावी है। इसके अलावा अगर हम अच्छी किताबें पढ़ने के साथ-साथ खुद में लिखने की आदत भी अपना लें तो इसका परिणाम और भी बेहतर मिलता है। आजकल, डॉक्टर किसी भी बड़ी बीमारी का इलाज करते समय साक्षरता को उपचार पद्धति के रूप में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि कई दवाओं के अक्सर दुष्प्रभाव होते हैं जो मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं।वे सिस्टम को प्रभावित करते हैं. इससे याददाश्त खोने

का डर रहता है. ऐसे में मरीज को पढ़ने-लिखने की सलाह दी जाती है, ताकि दिमाग सक्रिय रूप से काम कर सके। आज बदलते समय के साथ हमारी मित्र यानी किताबों का अंदाज और स्वरूप भी बदलने लगा है। जहां पहले किताबें पढ़ते समय उनकी भीनी-भीनी खुशबू हमारे दिमाग पर छाप छोड़ जाती थी, वहीं आज किताबें डिजिटल हो गई हैं और एक छोटे से उपकरण में हमारी जेब में फिट हो जाती हैं। हालाँकि, अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, तो वह वही हैयह उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि वे एक जगह बैठकर पढ़ और सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं क्योंकि इन्हें प्रकाशित करने में लाखों रुपये का खर्च आता है। मुद्रित पुस्तकों को साझा करके हम सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं।

किताबें इस बात का भी सबूत हैं कि कई प्रेमी जोड़ों ने एक-दूसरे से किताबें शेयर करते हुए इन किताबों के जरिए अपने दिल की बात कही है। आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से कुछ लोग हीएक क्लिक से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। यह और बात है कि आभासी दुनिया में केवल दस प्रतिशत लोग ही सच्चे दिल वाले होते हैं और उन्हें सच्चा प्यार मिल पाता है। यह भी देखें यह ज्ञात है कि इन प्लेटफार्मों पर लाभ के साथ-साथ हानि भी होती है।

जब प्यार किताबों पर आधारित होता था तो प्रेमी-प्रेमिका काफी मशक्कत के बाद अपने दिल की बात अपने पार्टनर तक पहुंचा पाते थे। इस पद्धति में यह डर रहता था कि पुस्तक प्रेमी के हाथ लगेगी या नहीं और उसे पढ़ने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कभी किताब में गुलाब डालो तो कभीमोर के पंख ऐसी कई भावनाएँ हमारी किताबों से जुड़ी हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी अगर हम अपनी किताबों को सीने से लगाकर रखें तो न जाने कितनी ही कही गई बातों की यादें ताजा हो जाएंगी। हर उम्र के साथ किताबों के मायने बदल जाते हैं। बचपन में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसे रंग-बिरंगी तस्वीरें ही नई दुनिया नजर आने लगती हैं। जैसे-जैसे वह युवावस्था में पहुंचता है, वह ज्ञान के भंडार की खोज करना शुरू कर देता है। फिर पाठ्यपुस्तकों से नहींसहायक पुस्तकें उसे अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करती हैं। युवावस्था तक पहुंचने तक, ज्ञान का संचय व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देना शुरू कर देता है। वयस्कता तक किताबें दिल और दुनिया की तस्वीर बन जाती हैं। बुढ़ापे में मुक्ति का रास्ता किताबों से होकर जाता है। दरअसल किताबें हमें हर दिन, शुरू से अंत तक कदम दर कदम चलना सिखाती हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हमें पुस्तकों से ही मिलता है। लेकिन आज व्यवसायीकरण के कारण किताबों में अश्लीलता फैल गई है। कौनक्योंकि युवा पीढ़ी लक्ष्य से भटक रही है। अच्छी किताबों से बढ़ती दूरी हमें नैतिक पतन, भौतिकवाद और मादक आधुनिकता का शिकार बना रही है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे में नियमित रूप से और स्वतंत्र रूप से पढ़ने और सीखने की आदत विकसित हो। पढ़ाई करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ें।

हवा स्वच्छ रखने में नागरिकों की की भूमिका

विजय गर्ग

सर्दी शुरू होते ही उत्तर भारत में एक बड़े हिस्से में स्वच्छ हवा लोगों की पहुंच से दूर होने लगती है। इस वैरान वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। इस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और नागरिकों की तरफ से सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2017 से भारत सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (ग्रेप) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और 15वें वित्त आयोग के 'मिलियन प्लस चैलेंज फंड' के तहत धन आवंटन जैसे कदमों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। हालांकि वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने के बावजूद अभी भी कई शहर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों की पार कर जा रहे हैं। सर्दियों के वैरान बारिश कम होने, हवा की गति धीमी होने और मिक्सिंग हाइट (यानी सतह से ऊपर की वह ऊंचाई जहाँ तक प्रदूषण तत्वों का फैलाव हो सकता है) घटने से प्रदूषण तत्वों के फंसने जैसी उत्तर भारत की मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण का बिखराव मुश्किल हो जाता है। इससे हवा में पार्टिकुलेट यानी अतिसूक्ष्म कणों का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) अधिक हो जाता है। इसलिए एकमात्र समाधन है कि सर्दियों के दौरान विभिन्न उत्सर्जनों में व्यापक कटौती की जाए।

सामूहिक व्यवहार में बदलाव

वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नागरिकों को अपने सामूहिक व्यवहार में ढांचागत बदलाव लाने चाहिए। इन बदलावों में यह शामिल है कि हम कैसे यात्रा करते है। इससे वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रभावित होता है कैसे हम कचरे का प्रबंधन करते हैं याने कचरा जलाते हैं या उसका विज्ञानिक विधि से निस्तारण करते हैं और कैसे खाना पकाते हैं या स्वयं को गर्म रखते हैं जिसके लिए हम अक्सर जैव ईंधन जलाते हैं, जिससे उत्सर्जन बढ़ता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने नागरिकों के लिए वायु प्रदूषण के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की एक सूचं दी है। ये कदम वायु प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रेप स्टेज 1 लागू होने के दौरान जब एक्यूआई खराब श्रेणी और 201-300 के बीच रहता है, नागरिकों से वाहनों की प्रदूषण जांच कराते हुए उन्हें अच्छी स्थिति में रखने जैसे उपाय करने का अनुरोध किया जाता है जब वायु गुणवत्ता ज्यादा बिगड़ जाती है और ग्रेप स्टेज 3 लागू होता है, तब सरकार नागरिकों को घर से काम करने का विकल्प चुनने की सलाह देती है। इन उपायों की सफलता में नागरिकों की और से इनका अनुपालन महत्वपूर्ण है।

प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की जानकारी

लोगों की प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की जानकारी देते हुए वायु गुणवत्ता प्रशासन में सक्रिय सहयोग करने की नागरिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नागरिक अपने साधारण मोबाइल फोन से नागरिक शिकायत निवारण एप के माध्यम से टूटी सड़कों, कूड़ा-कचरा जलाने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जैसे प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की जानकारी दे सकते हैं। देश के लगभग 130 शहरों में सिटी एक्शन प्लान के तहत इस उद्देश्य से आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से नागरिक वायु प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में में समीर, ग्रीन दिल्ली और एमसीडी 311 जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जी इन शिकायतों को देखते हैं। पिछले साल काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) ने पर्यावरण विभाग (जीएनसीटीडी) के साथ मिलकर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की सूची बनाने और प्राथमिकता निर्धारण की एक पद्धति तैयार की थी। यह उपाय अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल किया गया है। इस पद्धति का आधार शहर के सजग नागरिकों की और से सार्वजनिक शिकायत निवारण एप पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतें हैं। इस तरह के एप के बारे में जागरूकता और इनका उपयोग बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अभी इनका उपयोग बहुत ही सीमित है।

जनभागीदारी

भारत में वायु गुणवत्ता सुधरों के माध्यम से जोर देने के लिए धन उपलब्धता और राजनीतिक गतिशीलता दोनों ही मामलों में सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी मांग हमेश मौजूद रहेगी। हालांकि जागरूक और मुखर नागरिक अपने परिवार, समुदायें और इंटरनेट मीडिया पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए इसके महत्व में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि आस-पड़ोस में प्रदूषण स्त्रोतों से जुड़ी शिकायतों की संख्या काफी बढ़ जाती है, तो यह सजग नागरिकों की एक महत्वपूर्ण चिंता का संकेत होगा, जो संभावित रूप से राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे किसी पहल को जन आंदोलन में बदलकर सफल बनाया जा सकता है।

जवाबदेही

स्वच्छ हवा जितना एक मौलिक अधिकार है, उतना ही एक साझी जिम्मेदारी है। नागरिकों को वायु प्रदूषण के बारे में गंभीरता से विचार करन चाहिए और इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत की तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता की समस्या को दूर करने के लिए नागरिकों की न केवल अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, बल्कि इसे बेहतर बनाने वाले सामुदायिक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए। तभी हम प्रदूषण मुक्त सर्दियों का आनंद दोबारा हासिल सकते हैं, जो अभी प्रदूषण के साथ आती है।

दिखावे के रोग

विजय गर्ग

मध्यमवर्गीय समाज के कुछ लोग इन दिनों अनेक धनपतियों को देख-देख कर खुद को उनके जैसा ही दिखाने के भ्रम में कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। मासिक किस्त यानी 'ईएमआइ' के भरोसे अपने आप को 'रिच ' यानी धनी महसूस करने की मानसिकता में लोग मतवाले हुए जा रहे हैं। इस व्यामोह से कुछ किशोर और यहां तक कि बच्चे भी ग्रस्त दिखते हैं। पिछले दिनों एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले अपने बच्चे के बारे में अपनी सहेली को दुखी होकर बता रही थी कि मेरे बेटे को शहर के सिनेमा हाल में जाकर फिल्म देखना ही पसंद नहीं । उसे किसी माल में जाकर फिल्म देख कर ही संतुष्टि मिलती है और वहां जाने के बाद जब तक वह सात सौ रुपए वाला बड़ा पापकार्न खरीद कर न खाएं, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। ऐसा वह सिर्फ इसलिए करता है कि तब उसे 'रिच फीलिंग' (अमीर दिखने की अनुभूति) होती है। वह खुद को अनेक धनपतियों की श्रेणी में खड़ा पाता । वह किसी सामान्य दुकान से कपड़े नहीं खरीदता, बल्कि किसी बड़े माल में जाकर मशहूर ब्रांड के पैंट-शर्ट, जूते, घड़ी आदि खरीद कर पहनने का आदी हो चुका है। उसकी मां आए दिन बेटे की आनलाइन खरीदारी से भी परेशान हैं। घर में तीन-चार चश्मे पहले से पड़े हुए हैं। मगर उसे मोबाइल में आनलाइन कारोबार वाली किसी वेबसाइट पर कोई नया चश्मा पसंद आ जाएगा, तो फौरन आर्डर कर देगा। चमकदार जूते, घड़ी आदि नजर आते ही वह आर्डर कर देगा, भले ही ये सब चीजें उसके पास पहले से ही मौजूद हों। मां समझाती है, पर वह मानता नहीं ।

इस उद्धरण को सिर्फ संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है। सच यह है कि ऐसे बच्चे और उनकी ऐसी सोच-समझ और व्यवहार अब समाज में आम मामलों की तरह देखा जा सकता है। सक्षम तबकों से आने वाले ज्यादातर बच्चे इसी मानसिक ढांचे के तहत अपना जीवन-चक्र आगे बढ़ा रहे हैं । दिखावा एक सामाजिक मूल्य बनता जा रहा है।

मगर इस सबसे बेखबर समाज के दूसरे वर्ग भी दिखावे के इस रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं। एक नशा बाहर के खाने का भी है। अब अनेक बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आता, आनलाइन पिज्जा और ठंडे पेय मंगा कर खाना-पीना उसे खूब भाता है। आनलाइन खरीदी का नशा अलग है। ऐसे तमाम बच्चे हैं, जिनकी मां की एक बड़ी राशि बेटे की आनलाइन खरीदारी में चली जाती है। वह बार-बार समझाती है, लेकिन अमीर होने के अहसास होने से मार की वजह से यह बात समझ में नहीं आती कि मां को अपनी सीमित तनख्वाह के भरोसे महीने भर घर चलाना है। मां की आर्थिक दिक्कत से बेटे का कोई सरोकार नहीं । उसे अपनी अमीर होने की अनुभूति की चिंता है। मसलन, कभी-कभी आंदोलनकर्मी नारे लगाते हैं कि 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों'। इसी तरह, कुछ बच्चों की जिद रहती है कि भले ही माता-पिता के बैंक खाते में पैसे खत्म हो गए हों, मगर उन्हें जो चीज चाहिए तो वह चाहिए ही । इस तनाव में मां को मजबूरी में कहीं से उधार मांगना पड़ता है।

ऐसे अनेक बच्चे मध्यवर्गीय परिवारों में मौजूद हैं, जो आर्थिक हैसियत न होने के बावजूद सिर्फ इसलिए अनाप-शनाप चीजें खरीद लेते हैं कि उनकी 'रिच फीलिंग' बरकरार रहे। माता-पिता को कर्ज में डुबोकर बच्चे बड़े आत्मविश्वास में भरकर कहते हैं कि जब वे कमाने लगेंगे, तो महंगी कार खरीदेंगे, पूरी दुनिया की सैर करेंगे, भले ही अभी पुरानी कार खरीदने की भी आर्थिक हैसियत नहीं हो, मगर अमीरी के सपने देखने में कोई कमी नहीं । एक पिता अपने दो बेटों की इसी मानसिकता से त्रस्त थे कि उसके कारण ही वे कर्ज में डूबे हुए हैं। 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' वाली स्थिति है। ऐसे अहसास के शिकार वे बच्चे अधिक हैं, जो पढ़ाई-लिखाई को गंभीरता से नहीं लेते और हर समय स्मार्टफोन में नजरें गड़ाए रखते हैं। अब तो स्मार्टवाच भी है, जिसमें मनोरंजन के बहुत से इंतजाम हैं। ऐसे बच्चों की महंगी फरमाइशों को पूरा करते-करते अभिभावक परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को समझा ही नहीं पाते कि हम तुम्हारे अमीर होने के अहसास को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए भी नहीं करते कि कहीं इसका दुष्परिणाम न हो । आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें मां ने डांट दिया तो लड़का घर से भाग गया। महंगा मोबाइल नहीं दिलाया तो बच्चा फंदे से लटक गया।

सही है कि इस बाजारवाद की सबसे भयावह चीज यही है कि मध्यवर्गीय परिवार के अनेक बच्चे अपने अभिभावकों की परेशानियों को समझना नहीं चाहते । सिर्फ यह कि किसी भी सूरत में उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। जबकि बाजार सामान्य इच्छाओं को भी एक बेलगाम भूख में तब्दील कर देता है। अब तो महंगा आइ- फोन 'स्टेटस सिंबल' या ऊंची हैसियत का प्रतीक बन चुका है। मन में यह गर्वीला भाव जागृत होता है कि हम भी कुछ हैं। बच्चे स्कूल या कालेज में अपने साथियों को दिखाते हैं कि हमारे पास भी आइ-फोन है, भले ही उसकी मासिक किस्त भरते- भरते अभिभावक परेशान रहें। एक सवाल यह भी है कि बच्चों की सोच-समझ की इस दिशा में आगे बढ़ते जाने में क्या अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं बनती ? क्या बच्चों के भीतर अभिरुचि के विकास और उनके एक जिद में तब्दील होने में अभिभावकों की अनदेखी की कोई भूमिका नहीं है? हालांकि समझदार बच्चे घर-परिवार की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए कभी अनावश्यक जिद नहीं करते। वे दिखावे की होड़ में बिल्कुल नहीं पड़ते और यथार्थ में जीते हैं। जैसी चादर है, उसके हिसाब से पैर फैलाना चाहिए।

कम मेहनत से अधिक पढ़ाई के मंत्र

अभी एक स्टूडेंट हैं या फिर चाहे स्कूल-कालेज में पढ़ रहे हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। सभी को कुछ बुनियादी बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि विद्यार्थी की बात करें, तो वह दीपावली में जलते हुए एक दीपक की तरह होता है, जो लगातार अपने अध्ययन के प्रकाश के द्वारा अपनी अज्ञानता की कालिमा के विरुद्ध जूझता रहता है। इस तरह से देखा जाए, तो आप एक योद्धा भी हैं। आपको अपनी इस पहचान को हमेशा याद रखना चाहिए। यदि आप इसे याद रखे रहेंगे, तो इतना करने भर से आपके मन में उत्साह बना रहेगा। आप निराश और उदास नहीं होंगे आपके शरीर को आलस्य जकड़ नहीं पाएग आपका दिमाग एक सैनिक की तरह हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहेगा। वह तरोताजा बना रहेगा। ऐसे मन, ऐसे शरीर और ऐसे दिमाग से जो पढ़ाई होगी, वह कमाल की होगी। आप यह कमाल केवल इस छोटे से वाक्य को याद रखकर कर सकते हैं कि 'मैं एक ज्ञान योद्धा हूं।'

दूसरा तत्व है सफाई का हमारा घर चाहे जैसा भी हो, दीपावली पर हम उसकी सफाई करते ही हैं। इससे घर के कबाड़ से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हमें स्वच्छता का भी अनुभव होता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक बहुत बड़ी उपयोगी और व्यावहारिक बात कही थी। उनका कहना था कि जहाँ भी कूड़ा-कर्कट, सड़ी-गली और बेकार की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, उस स्थान से बड़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसके ठीक विपरीत जो स्थान जितना अधिक साफ-सुथरा होगा, प्रकाशवान होगा, वहाँ की ऊर्जा उतनी ही अधिक सकारात्मक होगी। इसलिए दीपावली के दिन तक हम सभी अपने-अपने घरों की साफ-सफाई, लिपाई पुताई करके उसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना देते हैं। कितनी अच्छी बात है न यह। मैंने इससे पहले आपसे कहा है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आप एक 'ज्ञानवीर' हैं, ज्ञान के योद्धा हैं। आप विचार कीजिए कि एक योद्धा को कितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नकारात्मक ऊर्जा हमें भगोड़ा बनाती है। यह हमारे मन को ही दुखी नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर को भी बीमार करती है। जब कोई आपसे आपके बारे में निगेटिव बात कहता है, तो आपको कैसा लगता है इसका अनुभव आपको है क्या आप ऐसे निगेटिव लोगों के साथ रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आते। उनकी बातों मेरा मनोबल कम होता है। मैं तनाव में चला जाता हूं। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहूंगा। आपका उत्तर होना भी यही चाहिए। यह तो हुई लोगों की बात स्थानों के बारे में आपकी राय क्या है, आपको चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई-लिखाई वाले स्थान को साफ-सुथरा रखें। उसे व्यवस्थित रखें। वहां हवा और प्रकाश आने दें। अपनी आलमारी और दराज से फालतू की चीजों को हटाते रहें और यह भी देखते रहें कि आपकी टेबल और किताबों पर धूल जमने न पाए, यानी झाड़-पोंछ भी करते रहें।

साथ ही खुद को भी साफ-सुथरा रखें। कपड़े धुले हुए हों। जूतों में पालिश होती रहे। नहाकर पढ़ने बैठने से एक अलग ही तरह की ताजगी का एहसास होता है। ऐसा करके आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को काफी बढ़ा सकते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क की ग्रहण शक्ति को काफी बढ़ा देती है। दरअसल, मुश्किल यह है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा काम केवल पढ़ाई करना है और वे इस काम में दिन रात लगे भी रहते हैं। लेकिन जब उन्हें अपनी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, तो वे निराश हो जाते हैं। आपको इसी निराशा को संभालने का गुर सीखने की जरूरत है। फिर देखिए, कामयाबी कैसे नहीं आपको मिलती है। इससे जीवन में जो सकारात्मकता आएगी, सो अलग।

महंगाई लक्ष्य के अनुरूप रखना जरूरी

चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में इस बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढना होगा। हम उम्मीद करें कि इन विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से देश में खुदरा महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई लक्ष्य के अनुरूप 4 .5 फीसदी तथा आगामी वर्ष 2025-26 में चार फीसदी के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी

यकीनन दीपावली के त्योहार के बाद भी नवंबर में प्याज और आलू के साथ अन्य सब्जियों के तेज दाम और खाने के तेल के दाम भी ऊंचे रहने से महंगाई बढ़ी हुई है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस समय देश में खाद्य कीमतों में वृद्धि से खुदरा महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। विदेशों से देश में आयात की जा रही विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में इजाफे से भी महंगाई बढ़ी है। ऐसे में महंगाई नियंत्रण के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लंबी अवधि तक ब्याज दर को स्थिर रख सकता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों की यथास्थिति, सरकार के महंगाई नियंत्रण के उपाय, अच्छे मानसून तथा स्थिर आपूर्ति श्रृंखला के अच्छे आधार के बावजूद सरकार को खुदरा महंगाई लक्ष्य के अनुरूप 4.5 फीसदी के दायरे में रखने की चुनौती के मद्देनजर नई बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढना होगा। गौरतलब है कि विगत 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.49 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अगस्त में 3.65 प्रतिशत थी। आलू, प्याज, टमाटर के साथ हरी सब्जियों की कीमतों में करीब 36 फीसदी वृद्धि तथा महंगी हुई दालों ने सितंबर माह में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर को नौ माह के उच्चतम स्तर 9.24 प्रतिशत पर पहुंचा दिया, जो कि माह अगस्त में 5.66 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से सितंबर में थोक महंगाई दर भी 1.84 प्रतिशत पर पहुंची है, जो कि माह अगस्त में 1.31 प्रतिशत थी।

खुदरा और थोक महंगाई मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि आलू, प्याज और टमाटर के दाम कम नहीं होने से जो खुदरा महंगाई दर पांच प्रतिशत के पार हो गई, वह इस माह नवंबर में भी पांच फीसदी के पार जा सकती है। हमें देश में महंगाई की चिंता इसलिए भी करनी है, क्योंकि वैश्विक बाजार में पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढने की आशंका बनी हुई है। चूंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादकों में से एक है और यह देश पश्चिम एशिया के संवेदनशील इलाकों में स्थित है, ऐसे में ईरान के तेल बाजार में अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढने पर पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने लगेंगे। इसका असर भारत पर विशेष रूप से पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों के करीब 80 फीसदी तक आयात पर निर्भर है। एक चिंताजनक बात यह भी है कि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष का असर वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भी पड़ सकता है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य पर। यह वैश्विक यातायात का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है। दुनिया को मिलने वाला करीब एक-तिहाई तेल और खाद्य व कृषि उत्पादों का अधिकांश यातायात इसी मार्ग से होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में शिपिंग बाधित होने से ग्लोबल सप्लाई चैन प्रभावित हो सकती है। इससे खाद्य पदार्थों, जैसे कि गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब एक बार फिर सरकार को महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी नई रणनीति की डगर पर आगे बढना

होगा। इस परिप्रेक्ष्य में विगत 9 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी कमेटी बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में महंगाई बढने के जोखिम के मद्देनजर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यह लगातार 10वीं बार है जबकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.50 प्रतिशत पर बरकरार है और बैंक रेट 6.75 प्रतिशत पर स्थिर रखी गई हैं। इस मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में तेज विकास दर की बजाय महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो माह बाद दिसंबर 2024 में भी आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने की स्थिति में नहीं होगा।

निश्चित रूप से इस बार देश में अच्छे मानसून से खाद्यान्न, दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी सप्लाई बढने से इनकी कीमतें कम होंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मौद्रिक प्रबंधन और सरकार के द्वारा तत्परता से खाद्यान्न निर्यात नीति और स्टॉक सीमा निर्धारण सहित विभिन्न उपाय बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण कर सकेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के करोड़ों किसानों को उनकी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में जो भारी बढ़ोतरी की है। उससे ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की मार झेल रहे किसानों को लाभ होगा। साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का जो इजाफा किया गया है, उससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक खाद्य महंगाई नियंत्रण के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के तहत की गई व्यवस्थाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए 10000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जहां इस कोष का उपयोग दाल, प्याज और आलू के बफर स्टॉक को रखने के लिए किया जाएगा, वहीं जरूरी होने पर इन अन्य खाद्य वस्तुओं के बढ़े दामों को नियंत्रित करने के लिए भी इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के बजट के तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए ऋणों की राशि दोगुनी करके 50000 करोड़ रुपए सुनिश्चित की गई है, जो उल्लेखनीय है।

निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के लिए सरकार के द्वारा तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालीन उपायों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी होगा। इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के बहुआयामी प्रयासों की कारगर रणनीति पर आगे बढना होगा। चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में इस बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढना होगा। हम उम्मीद करें कि इन विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से देश में खुदरा महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई लक्ष्य के अनुरूप 4.5 फीसदी तथा आगामी वर्ष 2025-26 में चार फीसदी के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी। ऐसी स्थिति से जहां देश के आम आदमी को राहत मिलेगी, वहीं अर्थव्यवस्था को भी गतिशीलता मिलेगी। महंगाई को रोकना वक्त की मांग है। मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित वर्ग है।

विस्तारा आज भरेगी आखिरी उड़ान, देश की पहली प्रीमियम एयरलाइंस की पूरी कहानी

परिवहन विशेष न्यूज

विस्तारा ने देश के हवाई यात्रियों को कई यादगार लम्हें दिए हैं। विस्तारा देश की पहली लग्जरी एयरलाइन थी लेकिन आज के बाद यह इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। आइए जानते हैं कि विस्तारा की शुरुआत कैसे हुई टाटा ग्रुप इसका मर्जर क्यों कर रहा है और अब मर्जर के बाद विस्तारा के ऑपरेशन का क्या होगा।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की विस्तारा आज आखिरी बार उड़ान भरेगी। इसका मंगलवार यानी 12 नवंबर, 2024 को टाटा ग्रुप की एयर इंडिया में मर्जर की प्रक्रिया हो जाएगी। अब एयर इंडिया देश की इकलौती फुल सर्विस कैरियर रहेगी। पिछले 17 साल में फुल सर्विस कैरियर की संख्या 5 से घटकर सिर्फ 1 रह गई। इस मर्जर के बाद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर एयर इंडिया का दबदबा बढ़ जाएगा।

एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर क्यों

एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन थी। इसकी शुरुआत 1932 में जेआरडी टाटा ने की थी। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। लेकिन, देश आजादी होने के बाद टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हो गया और इसे एयर इंडिया नाम मिला। टाटा ग्रुप को हमेशा अपनी एयरलाइन न होने की कमी खलती थी और उसने 2013 में विस्तारा को शुरू किया।

हालांकि, सरकार ने जब एयर इंडिया का निजीकरण करने का फैसला किया, तो टाटा ग्रुप ने भावनात्मक लगाव होने की वजह से उसे भी खरीद लिया। लेकिन, दो एयरलाइन का संचालन असहज करने वाला था, तो टाटा ग्रुप ने साल 2022 में विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर करने का फैसला किया। यह मर्जर आज से प्रभावी भी हो जाएगा।

अब विस्तारा के ऑपरेशन का क्या होगा?

अब 12 नवंबर से विस्तारा की सभी उड़ानों का संचालन एयर इंडिया करेगी। टिकट बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट से होगी। विस्तारा के 2.7 लाख ग्राहकों के टिकट एयर इंडिया को ट्रांसफर हुए हैं। लॉयल्टी मेंबर के प्रोग्राम महाराजा क्लब में ट्रांसफर होंगे। अब एयर इंडिया फुल-सर्विस और लो-कॉस्ट वाली पैसेंजर सर्विस, दोनों को ऑपरेट करने वाली इकलौती डोमेस्टिक एयरलाइन होगी। उसकी इंटरनेशनल रूट पर हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी से अधिक पहुंच जाएगी।

साथ ही, वह इंडिगो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन होगी। इस मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में हिस्सेदारी 25.1 फीसदी होगी, जो पहले विस्तारा में टाटा ग्रुप की साझीदार थी। मर्जर से एयर इंडिया का फ्लीट 144 से बढ़कर 214 विमानों का हो जाएगा। टाटा ग्रुप की लो कॉस्ट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास भी 90 विमान है। एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर भी दिया है।

विस्तारा ने कैसे बदली एविएशन इंडस्ट्री

- विस्तारा एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव लाई। यह एशिया की पहली एयरलाइन थी, जो फ्लाइट में स्टारबक्स कॉफी ऑफर करती थी।
- विस्तारा फ्लीट में एयरबस ए321 एलआर जोड़ने वाली और विमानों की सफाई रोबोट्स से करने वाली भी देश की पहली एयरलाइन थी।
- इसने इंटरनेशनल फ्लाइट में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू की। यह लॉयल्टी मेंबर्स को फ्री Wi-Fi देने वाली पहली एयरलाइन थी।
- विस्तारा ने 9 जनवरी 2015 से अपना ऑपरेशन शुरू किया। इसने सिर्फ सात महीने में ही 5 लाख से ज्यादा ग्राहकों हवाई यात्रा करा दी।
- विस्तारा ने अपने पूरे ऑपरेशन के दौरान 6.5 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवाएं दी। इसने करीब 12 देशों के लिए सीधी उड़ान भरी थी।
- फिलहाल यात्रियों को विस्तारा का अनुभव एयरक्राफ्ट, प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ मिलता रहेगा। इसमें फ्लाइट मेनू, कटलरी आदि हैं।
- अभी विस्तारा का लोगो भी नहीं बदलेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, सीट, पर्पल गिफ्ट कार्ड, फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम, एक्स्ट्रा लगेज स्पेस जैसी सुविधाएं रहेंगी।

म्यूचुअल फंड बेचने की जगह अब डिपॉजिट लाने पर बैंककर्मियों का जोर, क्या है इसकी वजह?

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैंकों में जमा की विकास दर कम होने पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। डिपॉजिट कम होने पर बैंकों से मिलने वाले कर्ज का संकट पैदा हो सकता है।

नई दिल्ली। पांच-सात साल पहले सरकारी बैंक के कर्मचारियों पर ग्राहकों को म्यूचुअल फंड (MF) बेचने का दबाव रहता था। अब यह स्थिति बदल गई है। अब बैंककर्मियों को किसी भी प्रकार से बैंक में जमा (Deposit) बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें बड़े-बड़े ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवा के माध्यम से अपने बैंक में डिपॉजिट के लिए लुभाने के लिए कहा जा रहा है।

सरकारी बैंक के कर्मचारियों को तो जमा (डिपॉजिट) बढ़ाने पर प्रोत्साहित करने की भी योजना चलाई जा रही है। जमा बढ़ाने वाले कर्मचारियों को बैंक के चेयरमैन या अन्य बड़े अधिकारियों से प्रशंसा पत्र या अन्य प्रोत्साहन पत्र देने की योजना बनाई जा रही है। तीन दिन पहले देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन एक कार्यक्रम में कहा था कि उनका पूरा ध्यान अभी बैंकों में डिपॉजिट बढ़ाना है।

आरबीआई गवर्नर के साथ देश की वित्त मंत्री भी बैंकों में जमा की विकास दर कम होने पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। डिपॉजिट कम होने पर बैंकों से मिलने वाले कर्ज का संकट पैदा हो सकता है। चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बैंकों की जमा विकास दर कर्ज कर्ज देने विकास दर से कम हो गई है।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक बैंक की जमा विकास दर में पिछले साल की तुलना में 11.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी, जबकि कर्ज देने की विकास दर 12 प्रतिशत से अधिक चल रही है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों की जमा विकास दर में पूर्व के वित्त वर्ष के मुकाबले 13.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष तक बैंककर्मियों का फोकस म्यूचुअल फंड बेचने पर रहा और बैंकों ने वित्त वर्ष 23-24 में व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों को 1.9 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड बेचा। पिछले तीन सालों में म्यूचुअल फंड का रिटर्न सालाना 15 प्रतिशत का रहा है जबकि बैंक के बचत खाते में 3.5-6 प्रतिशत का रिटर्न दिया जाता है। जमा राशि पर 10,000 रुपए से अधिक के ब्याज पर टैक्स भी लग जाता है।

चालू वित्त वर्ष से बाजार से लांग टर्म में होने वाली एक लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। ऐसे में कोई व्यक्ति शेयर बाजार में दस लाख रुपए लगाता है और उसे एक साल बाद 11 लाख रुपए में बेचता है तो उस एक लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बचत खाते में 10,000 रुपए से अधिक के ब्याज पर टैक्स लग जाता है।

डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर हुआ रुपया, क्या कर रहा है आरबीआई?

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले काफी समय से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रुपये में और भी ज्यादा गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। इससे आरबीआई पर भी जल्द कारगर कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। आइए जानते हैं रुपये में गिरावट की वजह।

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में यह 1 पैसा गिरकर 84.38 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। यह इसका अब तक सबसे निचला स्तर है।

क्यों गिर रहा है रुपया

करेंसी मार्केट के जानकारों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और इक्विटी मार्केट की सुस्ती के चलते रुपये में कमजोरी आ रही है। उनका कहना है कि जब तक डॉलर सूचकांक में नरमी नहीं आती या विदेशी फंड अपनी निकासी कम नहीं करते, रुपया दबाव में बना रहेगा।

रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 84.37 के नए ऑल टाइम लो-लेवल पर पहुंच गया था। इसमें लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई थी।

कब से दबाव में है रुपया

अमेरिकी चुनाव और लगातार विदेशी फंड की निकासी के बीच रुपया काफी समय से दबाव में है। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में करीब 12 बिलियन डॉलर की इक्विटी बिकवाली की थी। यह सिलसिला नवंबर भी में भी जारी है। उन्होंने नवंबर के शुरुआती 10 दिनों में ही करीब 1.6 बिलियन डॉलर की निकासी कर ली है।

सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित पाबारी का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार मूल्यांकन काफी अधिक है। साथ ही, कंपनियों के तिमाही नतीजे काफी कमजोर आ रहे हैं, जो ऊंचे वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते।

विदेशी निवेशकों ने कितनी निकासी की

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को 3,404.04 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। विदेशी निवेशकों ने सितंबर 2024 में 57,724 करोड़ रुपये का निवेश किया था। लेकिन, उन्होंने अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। यह उनकी अब तक की सबसे अधिक बिकवाली थी।

अगर नवंबर की बात करें, तो विदेशी निवेशकों ने पिछले पांच कारोबारी सत्रों में ही 20 हजार करोड़ रुपये की निकासी की है। एक्सपर्ट के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की बिकवाली आगे भी जारी रह सकती है। ऐसे में रुपये और शेयर मार्केट में अस्थिरता का दौर बना रहेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार में भी आई गिरावट

आरबीआई ने शुक्रवार को बताया था कि कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक नवंबर को खत्म सप्ताह में 2.675 अरब डॉलर घटकर 682.13 अरब डॉलर रह गया। पिछले सप्ताह कुल मुद्रा भंडार 3.463 अरब डॉलर घटकर 684.805 अरब डॉलर रह गया था। सितंबर के अंत में मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

हालांकि, रुपये में कमजोरी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। ऐसे में आरबीआई पर भी रुपये में गिरावट रोकने के लिए कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि आरबीआई चीनी करेंसी युआन के मुकाबले रुपये को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के वैल्यू में गिरावट की रणनीति बना सकता है।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी, भारी उतार-चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुए सेंसेक्स, निफ्टी

परिवहन विशेष न्यूज

एशियन पेंट्स टाटा स्टील बजाज फाइनेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा जेएसडब्ल्यू स्टील एनटीपीसी अडानी पोर्ट्स बजाज फिनसर्व और लार्सन एंड टूब्रो लाल निशान में बंद हुए। एशियन पेंट्स में सबसे अधिक 8 फीसदी की गिरावट आई। वहीं पावर ग्रिड एचसीएल टेक्नोलॉजीज इंफोसिस टेक महिंद्रा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में रहे। आइए जानते है कि कुल मिलाकर शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा।

नई दिल्ली। बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सपाट हुए। एफआईआई की लगातार बिकवाली, निराशाजनक तिमाही नतीजे और एशियाई बाजारों से कमजोर रुझानों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

बेंचमार्क सेंसेक्स भारी उतार-चढ़ाव से झूलने के बाद 9.83 अंक या 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,496.15 के स्तर पर बंद हुआ। इसने कारोबारी सत्र के दौरान 80,102.14 का हाई और 79,001.34 का लो बनाया। इसका मतलब कि इसमें 1,100.8 अंकों का उतार-चढ़ाव दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी 6.90 अंक या 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24,141.30 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों वाले शेयरों में एशियन पेंट्स में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। कंपनी ने शनिवार को बताया कि सितंबर तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 43.71 प्रतिशत घटकर 693.66 करोड़ रुपये रह गया। कमजोर मांग, सामग्री मूल्य मुद्रास्फीति और घरेलू बाजार में सजावटी और कोटिंग्स कारोबार में गिरावट के कारण यह गिरावट आई।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 3,404.04 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा कि भारतीय बाजार दबाव में हैं, जिसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ₹एफआईआई की बिकवाली भारतीय बाजार को आगे नहीं बढ़ने दे रही। विदेशी निवेशक कमजोर तिमाही नतीजों की वजह से निकासी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिकी मार्केट को लेकर उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हैं।₹

हालांकि, आईटी सेक्टर मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी आईटी खर्च में सुधार की उम्मीद के कारण बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।₹ नायर ने कहा कि भारत भी सीपीआई डेटा का इंतजार कर रहा है, क्योंकि खाद्य कीमतें मासिक आधार पर अधिक रहने की संभावना है। इससे आरबीआई को अल्पावधि में ब्याज दरों में कमी न करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

एशियाई बाजारों की बात करें, तो सियोल और हांगकांग में गिरावट आई, जबकि टोक्यो और शंघाई में तेजी रही। यूरोपीय बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट हरे निशान में बंद हुआ था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.83 प्रतिशत गिरकर 73.26 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शुक्रवार को बीएसई बेंचमार्क गेज 55.47 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,486.32 पर बंद हुआ। निफ्टी 51.15 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 24,148.20 पर आ गया।

रिन्यूएबल एनर्जी की बदलेगी दुनिया, सरकारी कंपनियां बना रहीं बड़ा गेम-प्लान

अभी तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र की धमक थी लेकिन आने वाले दो से तीन वर्षों मे सरकारी क्षेत्री की ऊर्जा कंपनियों का अलग महत्व होगा। उदाहरण के तौर पर ओएनीजीसी महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश समेत कुछ दूसरे राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने की कई संभावनाओं की समीक्षा कर रही है। इसमें सौर प्लांट से लेकर हाइब्रिड व छोटे पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल है।

नई दिल्ली। पिछले दिनों देश की ऊर्जा क्षेत्र की तीन दिग्गज कंपनियां ओएनजीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया (सीआईएल) की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर काफी अहम घोषणाएं की गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के सौर, पवन व दूसरे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी ओएनजीसी और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने हाथ मिलाया है।

वहीं, देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी सीआईएल ने अपनी 50वीं स्थापना दिवस मनाते हुए रिन्यूएबल सेक्टर में अपने विस्तार की बात स्वीकार की है। कंपनी वर्ष 2028 तक 5000 मेगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा से बनाने की योजना पर काम कर रही है।

दरअसल, इन सारी सरकारी कंपनियों की तरफ से की गई घोषणाएं केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति हिस्सा है, जिसमें वह अपनी पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों को कालांतर में रिन्यूएबल सेक्टर की बड़ी ऊर्जा कंपनी में तब्दील करना चाहती है।

सरकार के लिए यह काम इसिलए भी जरूरी हो गया है कि भारत में सौर, पवन व दूसरे रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में काफी इजाफा होने के बावजूद हम वर्ष 2030 के लक्ष्यों से काफी दूर हैं। हाल के महीनों में कई बाहरी एजेंसियों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इस बात की आशंका जता चुकी हैं कि अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भारत के लिए वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर से पांच लाख मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।

एक हफ्ते पहले ही नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में 396 फीसद की वृद्धि हुई है। सितंबर, 2024 में यह 2.10 लाख मेगावाट से ज्यादा हो गई है। सौर ऊर्जा की बिजली उत्पादन क्षमता 30 गुणा बढ़ कर 91 हजार मेगावाट के करीब हो गया है। इस हिसाब से अगले छह वर्षों में अतिरिक्त 2.90 लाख मेगावाट क्षमता जोड़नी है। यानी सालाना 50 हजार मेगावाट। जबकि वर्ष 2023-24 में भारत ने सिर्फ 19 हजार क्षमता ही जोड़ने में सफलता हासिल की है।

सूत्रों का कहना है कि अभी तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र की धमक थी लेकिन आने वाले दो से तीन वर्षों मे सरकारी क्षेत्री की ऊर्जा कंपनियों का अलग महत्व होगा। उदाहरण के तौर पर ओएनीजीसी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कुछ दूसरे राज्यों में रिनीवेबल ऊर्जा संयंत्र लगाने की कई संभावनाओं की समीक्षा कर रही है। इसमें सौर प्लांट से लेकर हाइब्रिड व छोटे पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल है।

अब कंपनी इसने ओएनजीसी के साथ मिल कर एक संयुक्त उद्यम बनाया है जो सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में नया निवेश करेगा। इन दोनों के गठबंधन की नजर अयाना रिन्यूएबल पावर पर है। दोनों कंपनियों की बराबर हिस्सेदारी (50:50) वाले संयुक्त उद्यम के गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है। जानकार बता रहे हैं कि इस अधिग्रहण के बाद भी यह संयुक्त उद्यम कुछ दूसरी रिन्यूएबल कंपनियों पर नजर रख रही हैं ताकि भविष्य में उनको खरीदा जा सके।

एनटीपीसी ने पहले ही रिन्यूएबल सेक्टर में उतर चुकी है और इसके लिए स्थापित सब्सिडियरकी एनटीपीसी ग्रीन के जरिए यह वर्ष 2032 तक इस सौर, पवन व दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से कुल 62 हजार मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य ले कर चल रही है।

सार्क की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है भारत ?

भारत अलग-अलग सार्क सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिससे अधिक बहुपक्षीय सफलता मिल सकती है। कनेक्टिविटी और व्यापार पर बांग्लादेश के साथ भारत के हालिया प्रयासों ने सार्क की सीमित प्रगति के बावजूद द्विपक्षीय सहयोग में सुधार किया है। भारत सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है, आम सहमति के बजाय बहुमत आधारित निर्णयों की वकालत कर सकता है, जो अक्सर प्रगति को रोकता है। भारत बिम्सटेक तंत्र के समान सुधारों का प्रस्ताव कर सकता है, जिसने क्षेत्रीय समझौतों में अधिक लचीलापन दिया है। भारत सार्क ढांचे के भीतर व्यापार सुविधा, संपर्क परियोजनाओं और निवेश को बढ़ाकर गहन आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास कर सकता है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

सार्क के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए लगातार पहल की है। हालांकि, भारत के प्रयासों के बावजूद, संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। भारत सार्क के भीतर आर्थिक सहयोग, संपर्क और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। भारत ने आतंकवाद और सीमा पार खतरों से निपटने के लिए सार्क के प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिसमें कई सुरक्षा सहयोग पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। भारत ने 1987 में आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन के निर्माण का नेतृत्व किया। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, कई चुनौतियों के कारण सार्क की प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। साफ्टा के बावजूद, अंतर-सार्क व्यापार 5% से कम बना हुआ है, जो खराब आर्थिक एकीकरण और सार्क की आर्थिक क्षमता को साकार करने में सीमित सफलता को दर्शाता है। आसियान के साथ भारत का व्यापार सार्क देशों के साथ उसके व्यापार से अधिक है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में सार्क की विफलता को रेखांकित करता है। प्रमुख राजनीतिक मतभेदों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच, ने शिखर-स्तरीय सहभागिताओं को बाधित किया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया रुक गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 2016 का सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो राजनीतिक सामंजस्य के टूटने का संकेत था। सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम सहमति की आवश्यकता होती है, जिससे पहल धीमी हो गई है, क्योंकि सदस्य देशों के बीच असहमति अक्सर प्रगति को रोक देती है।

पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण सार्क मोटर वाहन समझौता लागू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क प्रयास रुक गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने अक्सर सार्क की पहल को पटरी से उतार दिया है और इसकी समग्र प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। 2016 में उरी हमले के कारण भारत ने सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को और झटका लगा। सार्क सदस्यों, विशेष रूप से भारत और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक आर्थिक मतभेदों ने समान आर्थिक सहयोग हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद से आठ गुना अधिक है, जिससे व्यापार वार्ता और अपेक्षाओं में असंतुलन पैदा होता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षमता की कमी के कारण सार्क समझौतों को अक्सर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सार्क खाद्य बैंक का कम उपयोग होने के कारण व्यावहारिक प्रभाव बहुत कम रहा है।

कई सार्क देश आर्थिक और रणनीतिक सहायता के लिए चीन जैसी बाहरी शक्तियों पर निर्भर हैं, जिससे सार्क का आंतरिक सहयोग कमजोर हुआ है। नेपाल और श्रीलंका की चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ती निर्भरता ने सार्क की क्षेत्रीय एकता को कमजोर किया है। सार्क के पास निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सुपरनैशनल निकाय का अभाव है, जिससे यह क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में अप्रभावी हो गया है। यूरोपीय संघ के विपरीत, सार्क के पास निर्णयों को लागू करने या विवादों को हल करने के लिए अधिकार रखने वाले संस्थान नहीं हैं।

भारत अलग-अलग सार्क सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिससे अधिक बहुपक्षीय सफलता मिल सकती है। कनेक्टिविटी और व्यापार पर बांग्लादेश के साथ भारत के हालिया प्रयासों ने सार्क की सीमित प्रगति के बावजूद द्विपक्षीय सहयोग में सुधार किया है। भारत सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है, आम सहमति के बजाय बहुमत आधारित निर्णयों की वकालत कर सकता है, जो अक्सर प्रगति को रोकता है। भारत बिम्सटेक तंत्र के समान सुधारों का प्रस्ताव कर सकता है, जिसने क्षेत्रीय समझौतों में अधिक लचीलापन दिया है। भारत सार्क ढांचे के भीतर व्यापार सुविधा, संपर्क परियोजनाओं और निवेश को बढ़ाकर गहन आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास कर सकता है।

बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ परिवहन संपर्क पर भारत की बीबीआईएन पहल पाकिस्तान की अनिच्छा को दरकिनार करती है और उप-क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता को प्रदर्शित करती है। भारत सार्क देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक आदान-प्रदान और पर्यटन का लाभ उठा सकता है। सदस्य देशों के छात्रों के लिए भारत की सार्क छात्रवृत्ति ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। भारत को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश जारी रखना चाहिए जो पूरे क्षेत्र में संपर्क को बढ़ाते हैं, व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाते हैं। भारत-नेपाल रेल लिंक परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है, भले ही सार्क-स्तरीय पहल ठप हो गई हो।

संगठन की चुनौतियों के बावजूद सार्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सुधार के अवसर प्रस्तुत करती है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देकर और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर, भारत सार्क को पुनर्जीवित कर सकता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।

मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 10 कुकी उग्रवादी ढेर, दो सीआरपीएफ जवान जख्मी

रितेश राव

मणिपुर। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है. मणिपुर के जिरीबाम जिले के जकुराडोर में सोमवार को सीआरपीएफ के जवानों के साथ हुए मुठभेड़ में 11 कुकी उग्रवादी मारे गए तथा 2 जवान भी घायल हो गए. घायल सीआरपीएफ जवान को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया जिसमें एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना लगभग 3.30 बजे की है ज़ब कुकी उग्रवादियों नें पुलिस स्टेशन पर अचानक हमला कर दिया. उग्रवादी अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद से लैस एवं सैनिकों जैसी वर्दी में आए थे. पुलिस स्टेशन के नजदीक ही मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों के लिए एक राहत शिविर है। यहां रह रहे लोग लम्बे समय से कुकी उग्रवादियों के निशाने पर हैं. पुलिस के मुताबिक इलाके के पांच नागरिक भी लापता हैं. लापता नागरिकों की तलाश की जा रही है.

जिरीबाम के जकुराडोर में हुई घटना के पीछे बीते दिनों हुई घटना को कारण बताया जा रहा है, जहाँ संदिग्ध उग्रवादियों ने कुकी समुदाय प्रभुत्व वाले आदिवासी बस्ती जैरोन हमार गांव में तक़रीबन 10 घरों में आग लगा दी जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गई थी.

मणिपुर में पिछले एक साल से जारी जातीय हिंसा के कारण अब तक लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग राहत शिविर में रहने कों मजबूर हैं. मणिपुर में हिंसा का इतिहास जातीय और राजनीतिक संघर्षों से जुड़ा हुआ है. मणिपुर में 53 प्रतिशत मैतेई समुदाय के लोग हैं जो घाटी में रहते हैं, वहीं कुकी, नागा समेत 40 प्रतिशत आदिवासी पहाडी इलाकों पर रहते हैं। बता दें कि, कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की हाई कोर्ट की राज्य सरकार से सिफारिश के खिलाफ मार्च निकाला था, जिसके बाद से मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी जो अब तक शांत नहीं हो सकी है।

'चुनाव और शादी पर भी पटाखों पर लगे बैन' सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर उठाए कई सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना रखा है। सोमवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि पटाखों पर बैन को दीवाली से ही क्यों जोड़ा जाता है? शीर्ष अदालत ने कहा कि शादियों और चुनाव में पटाखे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दिल्ली के साथ अन्य राज्यों से अदालत ने रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को सोमवार को आड़े हाथों लिया। कहा कि सब दिखावा है। पटाखों पर प्रतिबंध को दीवाली से जोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे दीवाली से क्यों जोड़ते हैं? कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। यह लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। प्रदूषण मुक्त जीवन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लागू करने का निर्देश देते हुए इस बाबत तत्काल स्पेशल सेल गठित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पटाखों पर पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा और 25 नवंबर तक फैसला करके कोर्ट को बताने को कहा।

चुनाव और शादी पर पटाखों पर लगे बैन

शीर्ष अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ दिवाली ही नहीं, बल्कि सभी मौकों जैसे चुनाव और शादियों में भी लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीआर के अन्य राज्यों से भी पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक लगाने के बारे में जवाब देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और अगस्टिन जार्ज की पीठ ने सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिया।

सोमवार को कोर्ट ने पिछले आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार से दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में जारी आदेश और किए गए उपायों पर पूछा। दिल्ली सरकार ने हलफनामे का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि 14 अक्टूबर को सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने पूछा कि प्रतिबंध लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस प्रतिबंध लागू करती है।

दिल्ली पुलिस पर जताई नाराजगी

कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध ठीक से लागू नहीं किए जाने के लिए दिल्ली पुलिस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सब आंखों में धूल झोंकने जैसा है। पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, चलाने सब पर प्रतिबंध था। क्या इसे पूरी तरह लागू किया गया? आपने जो कुछ जब्त किया है वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी बंद करें।

दीवाली के दौरान पराली जलने के मामले बढ़ने पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली के दौरान पराली जलने के मामले बढ़ने पर भी सवाल उठाया। पराली जलाने के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के बजाय कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा है।

किसानों से कोर्ट ने क्या कहा?

उधर, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पर्यावरण कानून की धारा 15 के मुताबिक पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने राज्यों से उस पर अमल करने को कहा। सोमवार को कुछ किसानों की ओर से भी अर्जियां दाखिल की गईं और कहा गया कि सरकार उन्हें पराली के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं करा रही, लेकिन कोर्ट ने उन पर सुनवाई नहीं की।

विधायक बंडारी लक्ष्मारेड्डी और नगरसेवक जेरिपोटुला प्रभुदास ने मौलाली एचबी कॉलोनी राजस्थानी मारवाड़ी संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर बधाई दी

परिवहन विशेष न्यूज

दिनांक 09-11-2024 को विधायक बंडारी लक्ष्मारेड्डी एवं नगरसेवक जेरिपोटुला प्रभुदास ने राजस्थानी मारवाड़ी संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों को दिनांक 09-11-2024 को हुए चुनाव की पृष्ठभूमि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मौलाली एचबी कॉलोनी राजस्थानी मारवाड़ी संगम के नये अध्यक्ष के रूप में कैलाश का चयन सराहनीय है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैलाश राजस्थानी समुदाय के लोगों के लिए हर समय उपलब्ध हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं. इसीलिए राजस्थानी समुदाय के लोगों ने भी कैलासा को दोबारा अपना अध्यक्ष चुना. राजस्थानी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए कैलाश ने कहा कि वह उन सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्हें तीसरी बार राजस्थानी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना। उन्होंने नगरसेवक प्रभुदास के सहयोग से एचबी कॉलोनी में राजस्थानी समुदाय के सदस्यों के उत्थान के लिए काम करने का भी वादा किया। पूर्व पार्षद कोटा रामाराव, नेता गुम्मडी जम्पल रेड्डी, नवीन गौड़, कुमार, निसार अहमद गोरी, नरेंद्र राजस्थानी मारवाड़ी संगम के उपाध्यक्ष सोहन लाल सीरवी, मनोज शर्मा, सचिव दगलाराम, संयुक्त सचिव नरेंद्र सांकला, कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा, मीडिया प्रमुख पवन कुमार शर्मा कार्यक्रम में सलाहकार चेतन शर्मा बाबूलाल मुलेवा, दुर्गा राम , नारायण लाल परिहार, चेनाराम परिहार जी को बनाया गया।

कर्ज न चुका पाने पर ऑटो चालक ने की आत्महत्या, परिजनों ने की मुआवजे की मांग

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वरः कर्ज नहीं चुका पाने पर ऑटो चालक ने उसके गले में गमछा डाल दिया। ऐसी घटना कोणार्क-काकतपुर मुख्य मार्ग पर एनएसी पार्क के पास एक अर्धनिर्मित मकान में घटी। मृतक की पहचान कोणार्क थाने के कुरुजांग गांव के 51 वर्षीय प्रदीप्त महापात्र के रूप में की गई है। ऐसी घटना पुरी जिले के कोणार्क इलाके में घटी।जानकारी के मुताबिक प्रदीप्ता ने काफी समय से लाखों रुपये उधार ले रखा था। कर्ज समझ में न आने पर वह चिंतित था। चिंता की हालत में उसने रविवार की रात अपना गमछा फाड़कर गले में लपेटकर आत्महत्या कर ली। यह देख उसके परिवार ने पुलिस को सूचना दी। खबर पाकर कोणार्क थाने के अधिकारी पुनचंद्र सेठी मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर व्यक्ति के शव को कब्जे में लिया गया और मौत का मामला दर्ज किया गया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा है. इस घटना से उसकी पत्नी सदमे में है। हालांकि, ऑटो उपभोक्ताओं की ओर से आज पूरे कोने में ऑटो का परिचालन बंद कर दिया गया और मुआवजे की मांग की गयी। इसका समर्थन पूर्व सरपंच और मृतक के परिवार ने किया है।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री घोषित हुए वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल तथा प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल के आगरा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया तथा एक आवश्यक बैठक प्रान्तीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में होटल मानस में आहूत हुई।

बैठक में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तर प्रदेश की आगामी कार्ययोजना पर चर्चा से पूर्व सर्वप्रथम प्रान्तीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान के द्वारा संगठन व व्यापारी हित में किए हुए कार्यों को देखते हुए उनको प्रदेश मंत्री के पद पर मनोनीत किया। उन्होंने कहा, आशा है की आप संगठन व व्यापारी हित में अपने कार्यों से आप संगठन को नयी उचाइयों पर ले जाएंगे।

इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश मंत्री मुशरफ खान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। नवनियुक्त प्रदेश मंत्री मुशरफ खान ने कहा कि संगठन को मजबूत व गतिशील बनाना तथा व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करना मेरी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन अपना उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तर प्रदेश है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जिस लगन, ज़िम्मेदारी व मेहनत से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी काम करते है उसी का यह प्रतिफल है कि हम प्रदेश के बड़े संगठनों में एक है, और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों की एकता ही संगठन की मजबूती का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, सभी व्यापारियों के मान-सम्मान तथा स्वाभिमान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। शीघ्र ही सभी वर्गों के व्यापारियों को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तर प्रदेश का सदस्य बनाया जाएगा एवं व्यापारियों की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहेगा।

इस दौरान इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल तथा प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री कपूर चंद्र रावत, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, शहर अध्यक्ष नरेश पांडे, ओमप्रकाश वर्मा, प्रदीप कुमार अग्रवाल आदि उपस्थित सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

असमंजस में पड़ गए अजित

न जाने कैसे होता है सत्ता का मेल,
हर बार हो ही जाते उप-मुख्यमंत्री!
किस्मत में नहीं है बनना
मुख्यमंत्री।
असमंजस में पड़ गए अजित दादा,
वो महायुति का नहीं जानते इरादा।

दल का टूट ही गया वो पुराना
ढांचा,
राह चाचा की छोड़ बदल ली वाचा!
भले मिल गई घड़ी बदल गया
सांचा।
असमंजस में पड़ गए अजित दादा,
वो महायुति का नहीं जानते इरादा।

इस बंदे में कुछ है बात कुछ नाम
है,
कई बार खा गई है ये जनता
धोखा!
फिर भी देती है उन्हें हर बार
मौका।
असमंजस में पड़ गए अजित दादा,
वो महायुति का नहीं जानते इरादा।

एक बार फिर चाचा-भतीजा
सामने,
अब असमंजस में आ गई हैं
जनता!
किसे वोट दें किस पवार का नाम
ले।
असमंजस में पड़ गए अजित दादा,
वो महायुति का नहीं जानते इरादा।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, सूत्रधार व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023